घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 265- रविवार 26- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा

दीपके बोले...वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते,लेकिन झुकती है दुनिया,झुकाने वाला चाहिए

नई दिल्ली,25 जुलाई 2026। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है। इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा- वे कहते थे,इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते,लेकिन झुकती है दुनिया,झुकाने वाला चाहिए।प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की। दो पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ दो जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी।

12 साल में पहली बार विरोध के बाद इस्तीफा

2014 में पहली बार मोदी सरकार बनने के बाद 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान पहले मंत्री हैं, जिन्हें विरोध के चलते इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि,इससे पहले 2018 में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब दुनियाभर में 'मी टू' आंदोलन चल रहा था और अकबर पर पत्रकारिता के दिनों में यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे।

केजरीवाल बोले- सुनिश्चित करें कि भविष्य में कभी पेपर लीक न हो

अरविंद केजरीवाल ने कहा,'सब कहते हैं कि सरकार कभी झुकती नहीं है,पर इस सरकार को झुकना पड़ा। सरकार की यह जिम्मेदारी है ही कि वह प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग सुने। मैं उन्हें बधाई देता हूं। सरकारें अब यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कभी पेपर लीक न हो।

वांगचुक बोले...ये लोकतंत्र की जीत

सोनम वांगचुक ने अस्पताल से किए पोस्ट में लिखा...यह लोकतंत्र की जीत है,प्रत्यक्ष लोकतंत्र...सड़कों से मिली जीत। यह शांति,धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और GenZ को बधाई। देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद।

खड़गे ने कहा- प्रधान का इस्तीफा,सच की जीत,पीएम की हार

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवाज उठाने वाले करोड़ों युवाओं की जीत है। सच्चाई की जीत है। पीएम मोदी की जिद की हार है।' उन्होंने कहा, 'छात्रों के हित में संसद से लेकर सड़कों तक आवाज उठाने वाले एकजुट विपक्ष की जीत है। पीएम मोदी को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। लाठी और पैलेट गन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।'

दीपके बोले...कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है...

जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके ने कहा... मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है,लेकिन हमारी दो और मांगे हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच एक बार घुसता है, तो निकलता नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा मिले। पुलिसवालों पर एक्शन हो। दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखें कि उन्होंने कॉकरोच से पंगा लिया है। हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो तुम लोग क्या चीज हो। छात्रों पर केस वापस होने चाहिए। भैया,ये लोकतंत्र है। मुझे एक महीने से लोग कहते थे- क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे,ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये मनमानी सरकार है,लेकिन हमने कर दिखाया।

प्रियंका गांधी ने कहा...अब हर सरकार को जनता की सुननी होगी

प्रियंका गांधी ने कहा...बच्चों को लाठी से पीटा गया। आज के बाद इस देश का हर शासक याद रखेगा की आपको जनता की सुननी होगी। पूरे देश में छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये उनकी जीत है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी क्षमता से छात्रों का समर्थन किया। राहुल गांधी भी लगातार पिछले 2-3 सालों से छात्रों से मुद्दे पर डटे हुए हैं। आज आरएसएस ने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।

इस्तीफा सौंपते हुए धर्मेंद्र प्रधान बोले...देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं दूंगा...

मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त,समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं,भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई NEET-UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए whole of government approach के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही,छात्रों,अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से, इसपर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे,किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ।शिक्षण और कक्षा संसाधन मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं हैं,बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक,निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवाशक्ति ही,इस देश की असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं,देश की एकता बनी रहे,भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं,करियर बनाने पर फोकस करें,इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।दक्षिण-एशियाई और प्रवासी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन,विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही,मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों,मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ,जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्रीजगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता,ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूँगा।

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म

सरकार ने तीनों मांगें पूरी की...पहली-प्रधान का इस्तीफा दूसरी-प्रदर्शनकारियों से केस वापसी,तीसरी-मुआवजा

कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सौरभ दास ने कहा कि जंतर-मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर लौट जाएं। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई। हमारी तीनों मांगें मान ली गई हैं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सभी केस वापस लिए जाएं और नीट पीड़ितों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए शामिल हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आते ही जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रगान गाया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने स्टूडेंट्स के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा...प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन खत्म करें...

नड्डा ने कहा,'मित्रों,आज सौरव के साथ हमारी तीसरी बैठक हुई। आज भी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने चार पॉइंट दिए और उनकी मांगों पर चर्चा हुई। सबसे पहली मांग थी कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो,जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं, पांच बिंदुओं के प्रस्ताव पर हमारा कहना है कि परीक्षा सुधार के लिए चिंतन करेंगे और फिर इन्हें इसकी जानकारी देंगे। 'नड्डा ने कहा, 'सरकार ने मांगों को मान लिया है। मेरा निवेदन है कि प्रदर्शनकारी अपना आंदोलन खत्म करें। 'इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और कहा,'सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। इसलिए हम तुरंत प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हैं। आगे की जानकारी बाद में देंगे।

सौरव दास ने कहा...सरकार के साथ एक ड्राफ्ट भी साझा किया

सौरव दास ने कहा, हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट भी साझा किया है। इसे लिखित में मंगलवार तक देने का आश्वासन मिला है। एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग पर भी सहमति बनी है। यह राशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। हमने सरकार के सामने पांच बिंदुओं का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा सुधार पर चर्चा के लिए चार हफ्ते बाद फिर बैठक होगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि नीट से जुड़े आत्महत्या के मामलों में पीड़ितों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाएगा।

आशुतोष रांका ने कहा...हमारी तीनों मांगें मान ली हैं...

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा...पछले कुछ दिनों में सरकार से तीन बार बातचीत हुई। हमारी तीन मांगे थी...धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा,प्रदर्शनकारियों पर हुए केस वापस और भविष्य में कोई एक्शन न लिए जाएं। तीसरी डिमांड मृतकों को एक करोड़ मुआवजा देने की थी। हमारी पहली मांग पूरी हो गई है। दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर हटाने की थी, जिसे भी सरकार ने मान लिया है। 15-20 केस दर्ज हुए हैं,उनकी कॉपी सरकार हमारे साथ साझा करेगी। यह कॉपी तीन-चार दिन में मिल जाएगी। भविष्य में सीजेपी की टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार अब उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को सौंप गया है। प्रह्लाद जोशी ने 30 मई 2019 को पहली बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय उन्हें संसदीय कार्य,कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। जून 2024 तक उन्होंने इन मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। 2024 के आम चुनाव के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से प्रह्लाद जोशी लगातार पांच बार सांसद चुने जा चुके हैं।

15 मौतों वाली बिल्डिंग पर बड़ा एक्शन

100 पुलिसकर्मियों की निगरानी में ढहाई जा रही इमारत...

लखनऊ,25 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित उस कुख्यात अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को गिराने की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शनिवार को शुरू कर दी गई है, जहां बीते 22 जून को भीषण आग लगने के कारण 15 निर्दोष युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद से ही पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ था। एलडीए के विहित न्यायालय ने गत 10 जुलाई को इस अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करने का स्पष्ट आदेश जारी किया था। प्राधिकरण के आदेश के तहत भवन के मालिक वीरेंद्र शुक्ल और सुरेंद्र शुक्ल को यह निर्देश दिया गया था कि वे स्वयं अपने खर्च पर 15 दिनों के भीतर इस अवैध निर्माण को गिरा लें। स्वेच्छा से ध्वस्तीकरण न करने के कारण तय की गई अंतिम तिथि 25 जुलाई समाप्त होने के बाद, शनिवार को एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बुलडोजर और भारी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का औपचारिक आगाज किया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। ध्वस्तीकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं। इमारत के ऊपरी और मुश्किल हिस्सों तक बड़ी मशीनों और जेसीबी को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए पहले मलबे का एक मजबूत रैंप तैयार किया गया। इसके बाद प्रशिक्षित कामगारों और मशीनों की मदद से भवन के ऊपरी हिस्सों को जमींदोज करने का कार्य शुरू हुआ। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या व्यवधान को रोकने के लिए पूरे इलाके की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक-चौबंद कर दिया गया है। अलीगंज के सेक्टर-डी में स्थित भूखंड संख्या एमएस-102 पर लगे इस भवन के काले धब्बे और जली हुई दीवारें भले ही अब ध्वस्तीकरण के बाद जल्द ही हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी,लेकिन 22 जून की उस मनहूस रात से लोगों के दिलों-दिमाग में जो आग सुलग रही है, वह ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है। जिन विभिन्न विभागों के लापरवाह अधिकारियों और भ्रष्ट कर्मचारियों की घोर अनदेखी के कारण 15 बेकसूर युवा जलकर भस्म हो गए थे,घटना के पूरे 30 दिन बीत जाने के बावजूद उनके असली गुनहगारों का सुराग तक नहीं लग पाया है।

पेपर लीक मामलों पर बड़ा फैसला..भोपाल-इंदौर समेत 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट

नई दिल्ली,25 जुलाई 2026। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही धांधली,अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों की रोकथाम तथा उनकी त्वरित सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी एमपी हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के चार प्रमुख और बड़े शहरों–भोपाल, इंदौर,ग्वालियर और जबलपुर में चार विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों का आधिकारिक रूप से गठन किया है। यह नवनिर्मित विशेष अदालतें मुख्य रूप से 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' यानी पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज किए गए तमाम मामलों का बहुत ही तेजी से और समयबद्ध तरीके से निस्तारण करेंगी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अधिसूचना : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार, 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' की धारा 8 के उपखंड (3) के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का पूरी तरह से प्रयोग करते हुए अनुभवी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को इन नवनिर्मित विशेष अदालतों के संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत भोपाल शहर में प्रवीण पटेल (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश), इंदौर में विशाल अखंड (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश), ग्वालियर में आनंद कुमार सहलाम (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश), तथा जबलपुर में शुभ्रा सिंह (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) को इन विशेष अदालतों की कमान सौंपी गई है। देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और फर्जीवाड़े को लेकर छात्रों और युवाओं के बीच लगातार व्यापक विरोध-प्रदर्शन देखने को मिलते रहे हैं। युवाओं के इसी आक्रोश और न्याय प्रक्रिया को गति देने के लिए यह सख्त निर्णय लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले नकल माफियाओं, अपराधियों और आपराधिक गिरोहों पर नकेल कसने के लिए यह बहुत जरूरी था। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से ही इन विशेष अदालतों का गठन किया गया है।

कड़े कानूनों के तहत होगी मामलों की रोजाना आधार पर सुनवाई : इन विशेष अदालतों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि ये अदालतें नए और सख्त कानूनों के दायरे में रहते हुए सभी मामलों की दिन-प्रतिदिन यानी रोजाना के आधार पर सुनवाई करेंगी। पारंपरिक अदालती प्रक्रियाओं के चलते पूर्व में इस तरह के कई महत्वपूर्ण मामले वर्षों तक अदालतों में लंबित पड़े रहते थे, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते थे और पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। अब इन विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों के सक्रिय हो जाने से मुकदमों के वर्षों तक लटके रहने की पुरानी और जटिल समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार

भिवंडी,25 जुलाई 2026। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में विशेष जांच टीम ने इस अंतरराज्यीय रैकेट के मुख्य मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार से गिरफ्तार है। आरोपी को पटना से पुणे एयरपोर्ट और फिर वहां से भिवंडी लाया गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक मास्टरमाइंड समेत कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने साथी सोनू के साथ मिलकर प्रिंटिंग हाउस के कर्मचारियों को पैसों और अचल संपत्ति का लालच दिया था। इसके बाद साजिश के तहत प्रश्नपत्र को जूते के अंदर छिपाकर

प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया। शुरुआती तौर पर यह लीक पेपर महज आठ हजार रुपये में हासिल किया गया था, लेकिन इस गिरोह की योजना इसे भिवंडी और पुणे के बाजार में अभ्यर्थियों को लगभग डेढ़ करोड़ रुपये में बेचने की थी। भिवंडी पुलिस के डीसीपी पवन बंसोडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस निरीक्षक ने खुद 'नकली ग्राहक' बनकर आरोपियों से संपर्क साधा।

पेपर लीक पर नकेल : संसद में आज पेश होगा बिल

नई दिल्ली,25 जुलाई 2026। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार सोमवार को संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है।

सख्त सजा और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान : परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ अब कानून को बेहद कड़ा बनाया जा रहा है। नए ड्राफ्ट बिल के अनुसार, दोषियों के लिए न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम सजा 10 साल तक हो सकती है। इसके साथ ही, अपराधियों पर 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है, ताकि कोई भी आसानी से बच न सके।

संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना : पेपर लीक जैसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठित गिरोहों के लिए सरकार ने और भी कड़े प्रावधान तय किए हैं। यदि कोई गिरोह इस प्रकार के मामलों में शामिल पाया जाता है, तो न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे गिरोहों और दोषी संस्थाओं पर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे अपराधियों की आर्थिक कमर पूरी तरह टूट सके।

इस नए कानून की जरूरत? पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे लाखों मेधावी छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। पुरानी कानूनी व्यवस्थाओं में कमियों और लंबी न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाकर आरोपी अक्सर बच निकलते थे। छात्रों और अभिभावकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है, ताकि परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को फिर से बहाल किया जा सके।

जांच प्रक्रिया और फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था : इस नए संशोधन विधेयक में जांच प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत पेपर लीक के किसी भी मामले की जांच को 2 महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए देश भर में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दिया जाएगा।

संपादकीय

इस्तीफा अंत नहीं,शिक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटाने की शुरुआत होना चाहिए

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। लगातार छात्र आंदोलनों, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच उनका पद छोड़ना केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं,बल्कि जवाबदेही और लोकतांत्रिक दबाव की शक्ति का प्रतीक बन गया है। पिछले एक दशक में यह उन विरले अवसरों में से एक है,जब व्यापक जनदबाव के बीच केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री ने पद छोड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई बड़े जनआंदोलन देखे। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आंदोलन,कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का लंबा संघर्ष और अब प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर छात्रों का असंतोष–इन घटनाओं ने बार-बार यह साबित किया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को लंबे समय तक नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। इन आंदोलनों के कारण अलग-अलग रहे,लेकिन इनका साझा संदेश एक ही था–सरकार से जवाबदेही की अपेक्षा।

शिक्षा का क्षेत्र किसी भी राष्ट्र के भविष्य की नींव होता है। यदि परीक्षाओं की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े होने लगें,तो केवल लाखों छात्रों का भविष्य ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी कमजोर पड़ता है। हाल के महीनों में प्रतियोगी परीक्षाओं,विशेषकर नीट से जुड़ी कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने देशभर में छात्रों और अभिभावकों में गहरी चिंता पैदा की। विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया, वहीं छात्र संगठनों ने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल बताते हुए लगातार आंदोलन किए। बढ़ते दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की।

अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उनका निर्णय छात्रों के हित,राष्ट्रीय एकता और शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक व कानूनी विवादों से बचाने की भावना से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है। यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है,लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस्तीफे के बाद उन मूल कारणों का समाधान होगा, जिनकी वजह से यह स्थिति बनी। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या केवल मंत्री बदल जाने से परीक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियां दूर हो जाएंगी? क्या भविष्य में पेपर लीक,परीक्षा संचालन में गड़बड़ियां और पारदर्शिता से जुड़े सवाल समाप्त हो जाएंगे? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है,तो स्पष्ट है कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं,बल्कि पूरी व्यवस्था की है।

देश को अब ऐसी परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है,जिसमें तकनीकी सुरक्षा मजबूत हो,परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो,दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो और छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित किया जा सके। शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल प्रशासनिक बदलाव से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों से संभव होगा।

यह घटनाक्रम राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश है। सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि युवाओं की अपेक्षाएं पहले से कहीं अधिक हैं, जबकि विपक्ष के लिए भी यह अवसर केवल राजनीतिक लाभ लेने का नहीं,बल्कि शिक्षा सुधार पर ठोस सुझाव देने का होना चाहिए। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति से अधिक नीति की आवश्यकता है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जनता सवाल पूछ सकती है और सत्ता को जवाब देना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन इतिहास इस घटना को केवल एक इस्तीफे के रूप में नहीं,बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की शुरुआत के रूप में तभी याद रखेगा, जब सरकार पारदर्शी,विश्वसनीय और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। अन्यथा यह घटनाक्रम भी भारतीय राजनीति के अनेक प्रतीकात्मक इस्तीफों की सूची में दर्ज होकर रह जाएगा।

क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी?

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

भारत की शिक्षा व्यवस्था आज जिस मोड़ पर खड़ी है,वहाँ समस्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक मंत्रालय तक सीमित नहीं है। यह एक बहुस्तरीय संकट है,जिसमें नीतिगत अस्पष्टता,कार्यान्वयन की कमजोरी, संसाधनों की कमी, शिक्षक-प्रशिक्षण की चुनौती,परीक्षा-केंद्रित सोच और सामाजिक-आर्थिक असमानता–एक साथ मौजूद हैं। इसलिए जब यह सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी,तो इसका उत्तर केवल राज नीतिक नहीं,बल्कि संस्थागत और संरचनात्मक भी होना चाहिए। सच यह है कि केवल मंत्री बदल देने से शिक्षा व्यवस्था अपने-आप नहीं सुधरती; सुधार तब होता है जब नीति,नीयत, निवेश और निष्पादन,चारों एक दिशा में काम करें।

भारत में शिक्षा को लंबे समय से नीति से अधिक घोषणा के स्तर पर देखा गया है। हर सरकार शिक्षा सुधार की बात करती है,लेकिन ज़मीन पर परिवर्तन की गति बहुत धीमी रहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने का वादा किया था–समग्र शिक्षा,मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा,कौशल-विकास, बहु विषयी अध्ययन,डिजिटल लर्निंग और शोध-उन्मुख उच्च शिक्षा। कागज़ पर यह नीति अत्यंत महत्त्वाकांक्षी है। परंतु महत्त्वा कांक्षा और प्रभावी क्रियान्वयन के बीच अक्सर बहुत बड़ा अंतर रह जाता है। यही वह अंतर है,जहाँ किसी भी शिक्षा मंत्री की असली परीक्षा होती है।

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने, बहुभाषी शिक्षा पर बल देने,कौशल विकास को प्राथमिकता देने, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने और उच्च शिक्षा को अधिक लचीला बनाने की दिशा में कदम उठाए। यह कहना गलत होगा कि उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बहुत-सी योजनाएँ आगे बढ़ीं,संवाद बढ़ा,और शिक्षा पर राष्ट्रीय बहस तेज़ हुई। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल समस्याएँ जस की तस बनी रहीं। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता का अंतर,ग्रामीण-शहरी असमानता, शिक्षकों की कमी, परीक्षा -प्रधान संस्कृति,और कोचिंग-निर्भरता–ये सभी समस्याएँ अब भी गहरी हैं।

इसी संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा मंत्री की भूमिका क्या होती है। शिक्षा मंत्री न तो अकेले स्कूलों की गुणवत्ता सुधार सकता है,न ही विश्वविद्यालयों की शोध-क्षमता बढ़ा सकता है,और न ही एक झटके में करोड़ों विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति बदल सकता है। उसकी भूमिका मुख्यतः नीति-निर्माण,समन्वय,बजट प्राथमिकता,संस्थागत निगरानी और राज्यों के साथ सहयोग की होती है। यदि ये पाँचों काम बेहतर हों,तो शिक्षा में सुधार की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि केवल चेहरा बदल दिया जाए और नीतिगत ढाँचा वही रहे,तो परिणाम सीमित ही रहेंगे।

भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बराबरी का अवसर नहीं दे पाती। एक ओर महानगरों के निजी स्कूल और महंगे संस्थान हैं, जहाँ सुविधाएँ और अवसर अपेक्षाकृत अधिक हैं;दूसरी ओर सरकारी स्कूल और दूरस्थ ग्रामीण इलाके हैं,जहाँ बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और डिजिटल संसाधनों की भारी कमी है। इस असमानता को कोई एक मंत्री,चाहे वह धर्मेंद्र प्रधान हों या कोई और, अकेले समाप्त नहीं कर सकता। इसके लिए लंबे समय तक चलने वाली राज्य-नीति, केंद्र-राज्य समन्वय और सामाजिक निवेश की आवश्यकता होती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में शिक्षा सुधार का प्रश्न सिर्फ प्रशासनिक नहीं, वैचारिक भी है। दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा पास कराने वाली मशीन के रूप में देखी जाती रही है, न कि सोच विकसित करने वाले माध्यम के रूप में। रटंत शिक्षा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमता को सीमित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है,लेकिन बदलाव केवल दस्तावेज़ों से नहीं आता। इसके लिए पाठ्यक्रम,मूल्यांकन,शिक्षक-प्रशिक्षण और कक्षा-स्तरीय व्यवहार में परिवर्तन चाहिए। यही वह बिंदु है जहाँ सुधारों का वास्तविक परीक्षण होता है।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करने वालों का तर्क यह हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन से जवाबदेही बढ़ती है और नई ऊर्जा आती है। यह तर्क आंशिक रूप से सही भी है। किसी भी मंत्रालय में नेतृत्व की शैली, प्राथमिकताएँ और कार्य-संस्कृति महत्वपूर्ण होती हैं। यदि किसी मंत्री के कार्यकाल में संवाद कमज़ोर हो, नीतियों के परिणाम धीमे हों,या जमीनी स्तर की शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान न दिया जाए,तो बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन यहाँ भी प्रश्न यही है कि क्या बदलाव व्यक्ति में चाहिए या व्यवस्था में। यदि सिस्टम ही कमजोर हो, तो नया मंत्री भी उसी ढाँचे में काम करेगा। इसलिए इस्तीफ़ा केवल राजनीतिक प्रतीक बन सकता है, समाधान नहीं।

सच यह है कि शिक्षा सुधार की असली कुंजी बजट और क्रियान्वयन में छिपी है। भारत की शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश लंबे समय से अपेक्षाकृत कम रहा है। कई बार घोषणाएँ बड़ी होती हैं, लेकिन विद्यालयों की मरम्मत,प्रयोग शालाओं की स्थापना, पुस्तकालयों का विकास,छात्रवृत्ति वितरण,शिक्षक नियुक्तियाँ और डिजिटल पहुँच जैसे मूलभूत मुद्दे पीछे रह जाते हैं। यदि सरकार शिक्षा को वास्तव में प्राथमिकता देना चाहती है,तो उसे केवल नीति दस्तावेज़ नहीं, बल्कि वित्तीय प्रतिबद्धता भी बढ़ानी होगी। शिक्षा वह क्षेत्र है,जहाँ खर्च को बोझ नहीं,निवेश मानना चाहिए।

शिक्षक इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन भारत में शिक्षकों की स्थिति खुद संकटग्रस्त है। कई स्कूलों में शिक्षक-रिक्तियाँ हैं,कई जगह एक शिक्षक पर अनेक कक्षाओं का बोझ है,और कई संस्थानों में शिक्षक-प्रशिक्षण पुराना और अप्रासंगिक है। जब तक शिक्षक सक्षम, सम्मानित और प्रशिक्षित नहीं होंगे,तब तक कोई भी शिक्षा सुधार सीमित रहेगा। मंत्री बदलने से यह समस्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए सेवा-शर्तों में सुधार, प्रशिक्षण में गुणवत्ता,और शिक्षकीय पेशे को प्रतिष्ठा देने की ज़रूरत है।

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी सीमाएँ भी सामने आईं। महामारी के दौरान डिजिटल लर्निंग की उपयोगिता स्पष्ट हुई,पर यह भी उजागर हुआ कि देश के बड़े हिस्से में इंटरनेट, उपकरण और डिजिटल साक्षरता की भारी कमी है। अब डिजिटल शिक्षा को केवल गैजेट आधारित नीति नहीं, बल्कि समावेशी नीति बनाना होगा। इसका अर्थ है–ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी,कम लागत वाले उपकरण,स्थानीय भाषाओं में सामग्री, और शिक्षकों को तकनीक के लिए तैयार करना। केवल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना देने से शिक्षा आधुनिक नहीं हो जाती।

उच्च शिक्षा की बात करें तो भारत में शोध,नवाचार और अकादमिक स्वायत्तता अभी भी कई चुनौतियों से घिरी हैं। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम पुराना पड़ जाता है,शोध-फंड सीमित रहता है,और प्रशासनिक हस्तक्षेप अकादमिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। यदि शिक्षा मंत्री बदलने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता,अनुसंधान का वातावरण,और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार आता है, तभी उसका सकारात्मक अर्थ होगा। अन्यथा केवल राजनीतिक बयानबाजी से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता।

यह भी आवश्यक है कि हम शिक्षा सुधार को चुनावी बहस की तरह न देखें। शिक्षा एक लंबी प्रक्रिया है, जिसका परिणाम अगले दिन नहीं दिखता। किसी भी सरकार के लिए यह आसान होता है कि वह नई नीति की घोषणा कर दे, लेकिन मुश्किल यह है कि उसे दस साल तक निरंतर लागू करे। यहाँ निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हर मंत्री पिछली नीति को पूरी तरह बदलने लगे, तो शिक्षा व्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए सही प्रश्न यह नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जाएँ या रहें;सही प्रश्न यह है कि क्या कोई भी नेतृत्व शिक्षा को दीर्घकालिक राष्ट्रीय परियोजना की तरह देख रहा है।

भारत के लिए शिक्षा का अर्थ केवल रोज़गार नहीं,नागरिकता भी है। एक शिक्षित समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है,वैज्ञानिक सोच को बढ़ाता है, सामाजिक विषमता को चुनौती देता है और महिलाओं तथा वंचित समुदायों के लिए नए अवसर खोलता है। इसलिए शिक्षा सुधार को केवल सरकारी विभाग की प्रशासनिक उपलब्धि मानना गलत होगा। यह राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया में राजनीतिक स्थिरता,नीतिगत स्पष्टता और सामाजिक सहयोग है,तो बदलाव संभव है। वरना नेतृत्व परिवर्तन भी एक औपचारिकता भर बन जाएगा।

अंततः निष्कर्ष साफ़ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से शिक्षा व्यवस्था अपने-आप नहीं सुधरेगी। हाँ,यदि उनके स्थान पर आने वाला नेतृत्व अधिक संवेदनशील, अधिक जवाबदेह और अधिक परिणामो न्मुख हुआ,तो सुधार की गति बेहतर हो सकती है। लेकिन मूल सुधार मंत्री के जाने से नहीं,व्यवस्था के बदलने से आएगा। भारत की शिक्षा प्रणाली को चाहिए–स्थायी नीति,पर्याप्त धन, प्रशिक्षित शिक्षक,डिजिटल समावेशन,शोध-संस्कृति और सामाजिक समानता। यही वे आधार हैं,जिन पर वास्तविक सुधार खड़ा हो सकता है। चेहरा बदलना आसान है; व्यवस्था बदलना कठिन। और भारत की शिक्षा व्यवस्था को अब आसान नहीं,कठिन और ईमानदार सुधार की आवश्यकता है।

जब नारों में गालियाँ उतर आएँ

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

लोकतंत्र की सबसे सुंदर पहचान यह है कि यहाँ असहमति को अपराध नहीं माना जाता। यहाँ प्रश्न पूछना विद्रोह नहीं,बल्कि जागरूक नागरिक होने का प्रमाण है। सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहना,सत्ता से जवाब माँगना और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन वही आत्मा तब घायल होने लगती है जब नारों में विचारों की जगह गालियाँ उतर आती हैं,जब विरोध का स्वर मर्यादा छोड़कर अपमान का रूप धारण कर लेता है और जब क्रांति की भाषा सभ्यता से विमुख होकर कटुता की भाषा बन जाती है।

नारा केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं होता। वह किसी आंदोलन का चेहरा होता है,उसकी आत्मा का स्वर होता है। आने वाली पीढ़ियाँ आंदोलनों को उनके नारों से याद करती हैं। इंकलाब जिंदाबाद,करो या मरो, जय जवान,जय किसान जैसे नारे इसलिए अमर हुए क्योंकि उनमें किसी व्यक्ति का अपमान नहीं था,बल्कि एक विचार,एक संकल्प और एक युग की पुकार थी। शब्द जब उद्देश्य से जुड़ते हैं तो इतिहास बनते हैं, और जब वे केवल अपमान का माध्यम बन जाते हैं तो क्षणिक शोर से अधिक कुछ नहीं रह जाते।

आज का समय शोर का समय है। सोशल मीडिया ने हर आवाज़ को मंच दिया है,लेकिन साथ ही हर उत्तेजना को भी विस्तार दिया है। अब जो सबसे अधिक तीखा बोलता है,वही सबसे अधिक सुना जाता है। संयम को कमजोरी और शालीनता को निष्क्रियता समझने की भूल बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि कई आंदोलनों में तर्कों की जगह ताने, संवाद की जगह व्यंग्य और विरोध की जगह गालियाँ सुनाई देने लगी हैं। यह केवल भाषा का पतन नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक संस्कारों का क्षरण है।

गाली कभी भी विचार का विकल्प नहीं हो सकती। जिसके पास तर्क समाप्त हो जाते हैं,वह अक्सर अपशब्दों का सहारा लेता है। विचारों की लड़ाई में भाषा जितनी ऊँची होगी, आंदोलन उतना ही ऊँचा उठेगा। लेकिन यदि भाषा ही गिर जाए तो सबसे बड़ा उद्देश्य भी अपनी गरिमा खो देता है। किसी भी आंदोलन की नैतिक शक्ति उसके नारों की ऊँचाई से नहीं,बल्कि उसकी भाषा की गरिमा से मापी जाती है।

भारतीय सभ्यता ने वाणी को तप कहा है। हमारे ऋषियों ने कहा कि शब्द बाण भी बन सकते हैं और मरहम भी। वे समाज को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए वाणी पर संयम को चरित्र का आभूषण माना गया। राजनीति यदि समाज का दर्पण है तो आंदोलनों की भाषा उस दर्पण का प्रतिबिंब है। यदि प्रतिबिंब में केवल कटुता दिखाई दे रही है,तो यह केवल आंदोलन की नहीं,पूरे समाज की चिंता है।

यह भी सत्य है कि हर आंदोलन में हजारों-लाखों लोग होते हैं। कुछ व्यक्तियों के अनुचित व्यवहार से पूरे आंदोलन का मूल्यांकन उचित नहीं होगा। किंतु नेतृत्व की परीक्षा भी ऐसे ही क्षणों में होती है। भीड़ को दिशा देना केवल मंच से भाषण देने का कार्य नहीं,बल्कि उसकी भाषा को मर्यादित रखना भी नेतृत्व की जिम्मेदारी है। जो नेतृत्व अपमानजनक नारों पर मौन रहता है,वह अनजाने में उन्हें स्वीकार भी कर लेता है।

इतिहास बताता है कि सबसे प्रभावशाली आंदोलनों ने अपने विरोधियों को भी गरिमा से संबोधित किया। महात्मा गांधी का संघर्ष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था, ब्रिटिश जनता के विरुद्ध नहीं। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने तीखे मतभेदों के बावजूद संवैधानिक भाषा नहीं छोड़ी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, व्यक्तियों के अपमान की नहीं। यही कारण है कि उनके आंदोलनों की स्मृति सम्मान के साथ जीवित है।

आज आवश्यकता केवल सरकारों को बदलने की नहीं,बल्कि सार्वजनिक संवाद की भाषा को बचाने की है। लोकतंत्र संसद में जितना जीवित रहता है, उतना ही सड़कों पर भी साँस लेता है। यदि सड़क पर संवाद मर जाएगा,तो संसद की बहसें भी खोखली हो जाएँगी। यदि विरोध का अर्थ केवल अपमान रह जाएगा,तो सहमति की कोई संभावना नहीं बचेगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी संवाद है,और संवाद की पहली शर्त है–सम्मान।

हमें यह भी समझना होगा कि बच्चे और युवा केवल पुस्तकों से नहीं, समाज से भी सीखते हैं। जब वे टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर आंदोलनों में गालियाँ सुनते हैं,तो उनके मन में यह धारणा बनती है कि शायद यही संघर्ष की भाषा है। यह लोकतंत्र की अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि हम उन्हें विचारों की संस्कृति नहीं देंगे,तो वे शोर की संस्कृति को ही सामान्य मान बैठेंगे।

लोकतंत्र किसी की जीत और किसी की हार का नाम नहीं है। यह मतभेदों के बीच सह-अस्तित्व की कला है। यहाँ विरोधी शत्रु नहीं होता, केवल वैचारिक प्रतिद्वंद्वी होता है। इसलिए शब्दों की मर्यादा केवल भाषाई शिष्टाचार नहीं,बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रमाण है।

समय आ गया है कि हम अपने आंदोलनों को फिर से उनकी मूल आत्मा लौटाएँ। नारे ऐसे हों जिनमें विचार की चमक हो,आक्रोश हो तो भी संयम के साथ हो,असहमति हो तो भी सम्मान के साथ हो। क्योंकि इतिहास यह नहीं याद रखता कि किसने सबसे ऊँची आवाज़ में गाली दी थी,इतिहास उसे याद रखता है जिसने सबसे कठिन समय में भी अपनी भाषा की गरिमा बचाए रखी। लोकतंत्र तलवार की धार पर नहीं, शब्दों की विश्वसनीयता पर चलता है। यदि शब्द घायल हो जाएँ,तो संस्थाएँ भी देर तक सुरक्षित नहीं रह सकतीं। इसलिए जब अगली बार कोई आंदोलन सड़क पर उतरे, तो उसके हाथों में तख्तियाँ हों,आँखों में उम्मीद हो, आवाज़ में दृढ़ता हो–पर शब्दों में मर्यादा अवश्य हो। क्योंकि विचारों की विजय अपमान से नहीं,संवाद से होती है,और लोकतंत्र की सबसे ऊँची आवाज़ वही है जिसमें असहमति तो हो,लेकिन अमर्यादा न हो।

दिखावे की दानवीरता

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर,
बिहार

आज-कल दिखावे की दानवीरता पर हर रोज सम्मान बाँट रहा है। काम से ज्यादा सम्मान की चिंता हो गई है। शायद वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि कर्म करो, फल की चिन्ता मत करो तभी तो लोग आज कर्म से ज्यादा फल की चिन्ता करते हैं। एक समय था जब दान चुपके से होता था,सेवा निस्वार्थ भाव से होता है। अब तो दान का मतलब ही बदल गया है, सेवा का मतलब कैमरा,बैनर,माला,फोटो, अखबार की कटिंग हो गई । गरीब को 1 किलो चावल दिया और 100 फोटो खींच ली। मकसद पेट भरना नहीं, फेसबुक पर फोटो भरना रह गया और साथ ही दानवीरता के नाम पर सम्मान पाना हो गया है। जब एक समाज सेवी का सम्मान ही मकसद बन जाए तो दानवीरता / समाज सेवा भी व्यापार बन जाता है। स्टेज पर 10 मिनट का भाषण, गले में माला, हाथ में मोमेंटो। उसके बाद वही व्यक्ति मुड़कर उस गरीब को नहीं देखता जिसकी फोटो वायरल हुई थी ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये आज की हकीकत है।

आत्म-सम्मान,ख़ामोशी और रिश्तों का कड़वा सच

यह जीवन बहुत अनमोल है और इसे उन लोगों के पीछे रो-रोकर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो हमारी भावनाओं और हमारे वजूद की कोई क़द्र नहीं करते...

डॉ. मुश्ताक अहमद
'सहज'
हरदा,मध्यप्रदेश

जीवन का सफ़र बहुत लंबा और उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है,और इस रास्ते पर चलते हुए हमारा कई तरह के लोगों से पाला पड़ता है। कुछ रिश्ते हमारी रूह में गहराई से उतर जाते हैं, तो कुछ वक्त के साथ केवल एक ऐसा बोझ बन कर रह जाते हैं जिसे ढोना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में जब किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना पड़े जो कभी हमारे दिल के बेहद क़रीब हुआ करता था, तो यह फ़ैसला अत्यंत कठिन और दिल को चीर देने वाला होता है। यह साफ़ है कि मानवीय संबंधों में आत्म-सम्मान और अलगाव की एक अपनी ही सच्चाई होती है।

जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए और दूरियां आना पूरी तरह तय हो जाए,तो स्थिति को संभालने का सबसे बेहतर और परिपक्व रास्ता पूर्ण ख़ामोशी को अपनाना होता है। किसी रिश्ते को ख़त्म करने के बाद उस इंसान पर कीचड़ उछालना, समाज में उसे बुरा-भला कहना या उस पर बेवजह इल्जाम लगाना हमारे अपने संस्कारों,शालीनता और बड़प्पन को कम करता है। बेशुमार चाहत और बेइंतिहा मोहब्बत होने के बावजूद अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता,तो यह कड़वी सच्चाई जान लेनी चाहिए कि उस इंसान को न तो आपकी मौजूदगी की कोई परवाह है और न ही आपकी इस बेपनाह मोहब्बत की कोई ज़रूरत है।

इस परिस्थिति में स्वतंत्रता और जाने देने का फ़लसफ़ा सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जैसा कि कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को रोकना तो दूर,यह सवाल भी बिल्कुल मत करें कि वह आख़िर क्यों दूर हुआ, बल्कि उसे पूरी तरह से आज़ाद कर दें। जब कोई शख़्स अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर जाना चाहे या आपके एहसासों को अहमियत देना छोड़ दे, तो उसे जबरन रोकने की कोशिश करना खुद को मानसिक यातना और प्रताड़ना देने के समान है। उसे उसकी राह पर अकेला छोड़ देना ही बेहतर है,ताकि वह जहां और जिसके साथ भी रहना चाहे,अपनी मर्ज़ी से जी सके।

प्यार में जब कोई इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और बदले में उसे केवल उपेक्षा, नजर अंदाज़गी और दर्द मिलता है,तो उसका मन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे हालात में, उस क़द्र न करने वाले इंसान के लिए सबसे बड़ी और क़रारी सज़ा यही होती है कि आप उसे अपनी जिंदगी से इस तरह बाहर कर दें कि उसे आपका साया भी नसीब न हो । जो व्यक्ति आपकी क़ीमत नहीं समझता, उसे आपकी ग़ैर-मौजूदगी का अहसास कराना ही उसके सुधरने की उम्मीद या उसके उदासीन रवैये का सबसे बड़ा जवाब होता है।

अंततः,यह जीवन बहुत अनमोल है और इसे उन लोगों के पीछे रो-रोकर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो हमारी भावनाओं और हमारे वजूद की कोई क़द्र नहीं करते। जिस रिश्ते को छोड़ना मजबूरी या वक्त की मांग बन जाए, उसे पूरे सम्मान के साथ विदाई दें,अपनी ख़ामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और अपने स्वाभिमान व आत्म-सम्मान को हमेशा सर्वोपरि रखें।

पचास ग्राम का टुकड़ा

डॉ सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

उफ़! कितनी तपती धूप है आज,और उस पर यह पचास ग्राम का प्लास्टिक का टुकड़ा...यह सीने पर ऐसे चिपका है जैसे कोई मुजरिम छाती पर चढ़कर बैठ गया हो। इसे उतारकर जेब में रख लो तो मानो तुरंत दस डिग्री तापमान कम हो जाता है। हवा सीधे खाकी सूती कमीज़ के पार जाकर रीढ़ की हड्डी को सहलाने लगती है। नियम-कानून अपनी जगह हैं,पर इंसानी शरीर की भी तो कोई मर्यादा होती है या नहीं? आख़िर सिपाही भी तो इंसान ही है,कोई लोहे का खंभा थोड़े ही है जो हर मौसम में एक सा गड़ा रहे। इधर नेमप्लेट जेब में गई,उधर अचानक शरीर के भीतर की पूरी थकान काफ़ूर हो जाती है। जो हाथ दो मिनट पहले तक गर्मी के मारे ढीले पड़े थे,उनमें अचानक एक जादुई फुर्ती लौट आती है। सामने भीड़ है,शोर है, और हाथ में चिकनी,भारी नीम की लाठी। जैसे ही लाठी हवा में लहराती है, तो कोई यह नहीं देखता कि वो लाठी किसी बूढ़े की पीठ पर पड़ रही है या किसी नौजवान की पिंडली पर। लाठी का अपना कोई मज़हब नहीं होता,न ही उसकी कोई पहचान होती है। वह तो बस ऊपर से आए हुक्म का एक बेज़ुबान ज़रिया भर है, जो हवा को चीरती हुई सीधे गोश्त और हड्डियों के जोड़ पर जाकर टकराती है।

ज़मीन पर गिरकर कराहते हुए उस आदमी की आँखों में एक अजीब सा सन्नाटा तैर जाता है। वह फटी हुई आँखों से उस खाकी वर्दी के सीने को घूरता है, जहाँ एक आयताकार साफ़ निशान तो है,पर कोई नाम नहीं है। नाम होता, तो शायद वह अपने दर्द को एक नाम दे पाता। वह अदालत के दरवाज़े पर जाकर कह पाता कि मुझे फलां इंसान ने तोड़ा है। पर बिना नाम की खाकी तो बस एक अमूर्त सा साया बन जाती है। दर्द जब बेनाम हो जाए,तो वह और ज़्यादा जहरीला हो जाता है। इंसान सोचता रह जाता है कि जिस हाथ ने उसकी पसलियाँ तोड़ी हैं, उस हाथ के मालिक के घर में भी क्या छोटे-छोटे बच्चे होंगे जो शाम को उसकी उंगलियाँ पकड़कर घूमते होंगे?

सड़क के किनारे पड़े उस लहूलुहान इंसान के मुँह से निकली चीख दूर तक गूँजती है,पर वह खाकी के उस बेनाम सीने से टकराकर वापस लौट आती है। वर्दी के नियम भी बड़े दिलचस्प होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वे मोम की तरह पिघल जाते हैं और वक्त आने पर पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। जब अपने बचाव की बात आए तो खाकी सिर्फ़ एक नौकरी बन जाती है, और जब सामने वाले को कुचलने की बात आए तो वही खाकी असीम अधिकार का रूप ले लेती है। कानून की किताबें तो मेज़ पर बंद पड़ी रह जाती हैं, और सड़क पर बहता हुआ लाल खून धीरे-धीरे उड़ती हुई धूल में जज़्ब होने लगता है। शाम ढलते-ढलते जब मुआयने का वक्त आता है, तो वही प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े जेबों से बाहर निकल आते हैं। सीने पर सुरक्षा मानकों के हिसाब से दोबारा सजा लिए जाते हैं। अब वे सब के सब फिर से वही कानून के रखवाले बन चुके हैं,जिनकी आँखों में एक अजीब सी मासूमियत तैर रही होती है। उनके चेहरों पर न तो दिन भर के खून के धब्बे दिखाई देते हैं और न ही किसी बेबस की हाय का कोई निशान। जो दर्द उस सड़क पर छूट गया, वह सिर्फ़ उस इंसान का था जिसकी हड्डियाँ चटकी थीं,और उस लाचार व्यवस्था का था जो हर बार अपनी सुविधा के हिसाब से अंधी और बहरी हो जाती है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

प्रेम

उदय किशोर साह जयपुर बांका बिहार

प्रेम ना कोई छ्ल है ना कोई माया
प्रेम है खुशियों का पावन उद्दान
प्रेम मन की प्रफुल्लित वो कलियां है
प्रेम है थका जीवन का विश्राम
प्रेम दो मन की मिलन स्थल है
प्रेम है रब की अनुपम वरदान
प्रेम में दौलत वर्जित है प्रियवर
प्रेम है निश्छल पावन गंगा समान
प्रेम में ना छ्ल ना कोई कल बल है
प्रेम है ईश्वर का अनुठा अनुदान
प्रेम के वश में हर दिल की धड़कन है
प्रेम के वश में मेरे इष्ट मेरे भगवान
प्रेम ढाई आक्षर का संयोग है मित्रों
प्रेम से आलौकिक है ये जहान
प्रेम गम की संजीवनी बनी है
प्रेम है मन की तरंग का ज्ञान विज्ञान
प्रेम नर नारी की दर्शनशास्त्र है
प्रेम संवेदनाओं की है एक मुस्कान
प्रेम दो दिल की जवां धड़कन है
प्रेम दो जिस्म का एक है प्राण
प्रेम दीप है प्रेम ही प्रदीप है
प्रेम है मानवता का प्यारी जहान
प्रेम प्यार है प्रेम सर्मपण है
प्रेम है जीवन जीने की अरमान

आधे घंटे की जगह 5-10 मिनट पानी,आधी क्षमता पर चल रहे फिल्टर प्लांट! कांग्रेस के निरीक्षण में खुलीं जलापूर्ति व्यवस्था की कई परतें

17.5 और 18 एमएलडी क्षमता वाले प्लांटों से कम उत्पादन,खराब उपकरण,एलम की कमी और स्टाफ का अभाव...कांग्रेस ने नगर निगम पर लगाया बदइंतजामी का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में लगातार गहराते पेयजल संकट के बीच नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। कई वार्डों में आधे घंटे की बजाय केवल 5 से 10 मिनट पानी आने,कम दबाव और गंदे पानी की शिकायतों के बीच कांग्रेस पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में तकिया और कतकालो फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि जल संकट का कारण केवल बिजली कटौती नहीं,बल्कि फिल्टर प्लांटों का खराब रखरखाव,तकनीकी खामियां और प्रशासनिक लापरवाही भी है। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम प्रशासन अब तक बिजली कटौती को जल संकट का मुख्य कारण बताता रहा,लेकिन मौके पर निरीक्षण और लॉग बुक के अवलोकन से कई ऐसी कमियां सामने आईं,जिनके कारण शहर की जलापूर्ति क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने दावा किया कि 17.5 एमएलडी क्षमता वाले तकिया फिल्टर प्लांट से केवल 10 से 11 एमएलडी तथा 18 एमएलडी क्षमता वाले कतकालो प्लांट से केवल 12 से 13 एमएलडी पानी का शोधन और वितरण किया जा रहा है। यानी दोनों संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता से काफी कम उत्पादन कर रहे हैं, जिसका सीधा असर शहर की जलापूर्ति पर पड़ रहा है।

फिल्टर बेड पर काई-घास,महीनों से सफाई नहीं...

निरीक्षण में यह भी सामने आने का दावा किया गया कि फिल्टर प्लांट का एक महत्वपूर्ण मड पंप लंबे समय से खराब पड़ा है। वहीं फिल्टर बेड की महीनों से सफाई नहीं होने के कारण उस पर काई और घास तक जम गई है। कांग्रेस का आरोप है कि इससे जल शोधन क्षमता प्रभावित हो रही है और पानी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है।

32 कर्मचारियों की जगह मिले सिर्फ 6

कांग्रेस नेताओं के अनुसार अनुबंध के तहत दोनों प्लांटों में तीन शिफ्टों में कुल 32 कर्मचारियों की तैनाती होनी चाहिए,लेकिन निरीक्षण के दौरान दोनों प्लांटों में कुल मिलाकर केवल छह कर्मचारी ही कार्यरत मिले। कांग्रेस ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि इतने कम स्टाफ के भरोसे शहर की पेयजल व्यवस्था संचालित नहीं की जा सकती।

एलम का तीन महीने नहीं,सिर्फ तीन-चार दिन का स्टॉक : निरीक्षण में जल शोधन के लिए उपयोग होने वाले एलम (फिटकरी) का पर्याप्त भंडारण भी नहीं मिला। कांग्रेस का दावा है कि जहां कम से कम तीन महीने का स्टॉक होना चाहिए, वहां केवल तीन से चार दिन का स्टॉक उपलब्ध था। बरसात में नदी का पानी अधिक मटमैला होने से एलम की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में रसायन उपलब्ध नहीं होने से पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई गई।

जनरेटर होने के बावजूद नहीं होता उपयोग

निरीक्षण में यह भी आरोप लगाया गया कि बिजली बंद होने की स्थिति में उपलब्ध जनरेटर का नियमित उपयोग नहीं किया जाता, जिससे जलापूर्ति और अधिक प्रभावित होती है।

तीन क्लैरिफ्लोकुलेटर बंद, स्पेयर पार्ट तक नहीं

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों प्लांटों में कुल छह क्लैरिफ्लोकुलेटर में से तीन लंबे समय से बंद हैं। इसके अलावा कतकालो प्लांट में कोई उपकरण खराब होने पर उसके पुर्जे पुणे या मुंबई से मंगाने पड़ते हैं,जबकि स्थानीय स्तर पर आवश्यक स्पेयर पार्ट्स का भी भंडारण नहीं किया गया है। इससे मरम्मत में कई सप्ताह लग जाते हैं और जलापूर्ति प्रभावित होती है।

कलेक्टर से करेंगे शिकायत

नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने आरोप लगाया कि नगर निगम के सत्तापक्ष और प्रशासन की उदासीनता के कारण शहर की पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते फिल्टर प्लांटों का रखरखाव,उपकरणों की मरम्मत और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती तो नागरिकों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस पार्षदों ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात कर निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं की शिकायत करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, फिल्टर प्लांटों की तत्काल मरम्मत और शहर में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग करने की बात कही है।

मल्टीपरपज़ स्कूल में किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम स्वास्थ्य,स्वच्छता और साइबर सुरक्षा पर दिया गया मार्गदर्शन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय मल्टीपरपज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अंबिकापुर में लगभग 200 छात्राओं के लिए किशोरी स्वास्थ्य एवं जागरूकता विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलाव,मानसिक स्वास्थ्य तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में संकल्प हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकिता गोयल ने कहा कि मासिक धर्म प्रत्येक किशोरी और महिला के जीवन की सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इसे लेकर किसी प्रकार की झिझक या भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, सैनिटरी पैड का सही उपयोग,संतुलित एवं आयरन युक्त आहार लेने तथा नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही अत्यधिक दर्द, अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव जैसी समस्याओं को नजरअंदाज न कर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही। डॉ. गोयल ने परीक्षा के तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली पर भी छात्राओं से चर्चा की। उन्होंने समय प्रबंधन,पर्याप्त नींद,नियमित व्यायाम तथा परिवार और शिक्षकों से संवाद बनाए रखने को मानसिक तनाव कम करने के प्रभावी उपाय बताया। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर भी विशेष जानकारी दी गई। छात्राओं को सोशल मीडिया

का सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और डिजिटल माध्यमों पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञ ने सरल एवं वैज्ञानिक तरीके से उत्तर दिया। अंत में विद्यालय परिवार की ओर से शैलेन्द्र सेंगर ने डॉ. अंकिता गोयल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्राओं के सर्वांगीण विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने भी इसे उपयोगी बताते हुए भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले जिले के विद्यार्थियों को स्कूलों में ही मिलेगी ऑनलाइन क्लास की सुविधा

आगामी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए प्रारंभ से ही प्रभावी कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में सैनिटरी पैड प्रदाय के निर्देश

पीवीटीजी समुदाय के बच्चों को अगली कक्षाओं में प्राथमिकता के साथ प्रवेश दिलाने के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों,शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल,जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा,सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी,प्राचार्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है,इसलिए प्रारंभ से ही सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाए ताकि जिले के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके तथा आगामी

परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए और पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों की सतत समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

जिले के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस : कलेक्टर श्री वसंत ने निर्देशित किया जिले के छात्र-छात्राएं मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अब जिले के सभी हायर सेकेंडरी विद्यालयों में ग्यारहवीं के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं विद्यालय प्राचार्यों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी,पृथक कक्ष,बड़ी स्क्रीन सहित सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित की जाए,ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। उन्होंने रायपुर में नीट एवं जेईई की तैयारी कर रहे जिले के विद्यार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग एवं फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बार-बार प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए तथा नियमित टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। कलेक्टर ने भवन विहीन एवं विद्युत विहीन विद्यालयों की जानकारी लेते हुए उनकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक कार्यवाही कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उन्होंने विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों एवं गणवेश की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर पर्याप्त संख्या में वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालयों में स्थापित न्यूज डेस्क की जानकारी लेते हुए कहा कि विद्यार्थियों में समाचार पत्र पढ़ने की आदत विकसित की जाए, जिससे उनमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषयों की समझ बढ़े।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा,दो चालकों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

ब्रेथ एनालाइजर जांच में दोनों चालक मिले नशे में,न्यायालय ने प्रत्येक पर लगाया 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल चालक और एक कार चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दोनों मामलों में न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस तरह कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान चेकिंग के समय जेएच-01-डीबी-9302 क्रमांक की मोटरसाइकिल के चालक बृजकिशोर सिंह यादव (34 वर्ष),निवासी गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) को रोका गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। इसी अभियान के दौरान यूपी-61-एडी-2493 क्रमांक की कार के चालक वीरेंद्र गिरी (19 वर्ष), निवासी नवानगर, थाना दरिमा की भी जांच की गई। ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में वह भी शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये, कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

नाबालिग से बलात्कार का आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले की एक नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर युवक ने उसके साथ बलात्कार किया था। घटना वर्ष 2022 की है। पुलिस ने आरोपी विमल खाखा पिता निर्मल खाखा निवासी दातीढाप नर्मदापुर थाना कमलेश्वरपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था। वहीं मामले की सुनवाई कमलेश जगदल्ला, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर में चल रहा था। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाऊ 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है।

अस्पताल से रिहा हुए बंदी की दो घंटे बाद मौत

अच्छे आचरण पर दो वर्ष की सजा हुई थी माफ,लूज मोशन की शिकायत पर भर्ती था मेडिकल कॉलेज अस्पताल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

केंद्रीय जेल अंबिकापुर से रिहा किए गए एक आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी की रिहाई के करीब दो घंटे बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। बंदी बीमारी के कारण पहले से अस्पताल में भर्ती था और नियमानुसार उसे जेल के बजाय अस्पताल से ही रिहा किया गया था। घटना के बाद परिजन उसे घर ले जाने के बजाय पार्थिव शरीर लेकर लौटे। गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खलिबा निवासी 66 वर्षीय श्यामजतन साय दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वर्ष 2022 में सजा सुनाए जाने के बाद से वह केंद्रीय जेल अंबिकापुर में निरुद्ध था। जेल प्रशासन के अनुसार अच्छे आचरण और कार्यकुशलता के आधार पर शासन ने उसकी दो वर्ष की सजा माफ कर दी थी। इसके बाद 24

जुलाई को दोपहर 12.30 बजे उसकी रिहाई निर्धारित थी। रिहाई से एक दिन पहले 23 जुलाई की शाम उसकी तबीयत बिगड़ गई। पेचिश (लूज मोशन) की शिकायत होने पर उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। निर्धारित समय पर 24 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे जेल प्रशासन ने अस्पताल में ही रिहाई की औपचारिकताएं पूरी कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इसके करीब दो घंटे बाद दोपहर 2.30 बजे उसकी मौत हो गई।

बेटी लेने पहुंची, लेकिन शव लेकर लौटी : रिहाई से पहले जेल प्रशासन ने श्यामजतन की बेटी सानिया को सूचना देकर अस्पताल बुलाया था। वह पिता को घर ले जाने पहुंची थी, लेकिन रिहाई के कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। ऐसे में उसे पिता का पार्थिव शरीर लेकर लौटना पड़ा।

जेल में अच्छे व्यवहार पर मिली थी राहत : केंद्रीय जेल अधीक्षक अक्षय राजपूत ने बताया कि श्यामजतन का जेल में आचरण संतोषजनक था। इसी कारण शासन ने उसकी दो वर्ष की सजा माफ की थी। रिहाई की सूचना मिलने पर वह काफी खुश था। उन्होंने बताया कि यदि किसी बंदी की रिहाई के समय वह अस्पताल में भर्ती रहता है तो नियम के अनुसार उसे दोबारा जेल नहीं लाया जाता, बल्कि अस्पताल से ही रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंप दिया जाता है। श्यामजतन के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।

महामाया पहाड़ पर मिली महिला की सड़ी गली लाश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के महामाया पहाड़ पर महिला की सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। मृतका का शिनाख्त नहीं हो सका है। शव लगभग 1 माह पुराना बता जा रहा है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच की और शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस मृतका की पहचान में जुटी है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के ओपीएस स्कूल के करीब 100 मीटर दूर महामाया पहाड़ के जंगल वनकर्मी ड्यूटी कर रहे थे। वनकर्मियों ने एक महिला की लाश सड़ी गली हुई

स्थिति में देखी। लाश का आधा हिस्सा फांसी पर लटका था। वनकर्मियों ने इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। सचूना पर कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। विधिवत जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी भुलाया गया और जांच की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार शव लगभग 1 माह पुराना बताया जा रहा है। शव सड़ जाने के कारण हत्या या आत्महत्या की पुष्टी नहीं हो पाई है।

बेहतर शिक्षण नवाचार के लिए 4 शिक्षकों को मिला शिक्षा गौरव सम्मान

ज्ञानदीप पुरस्कार से अंजली सरिता बड़ा सम्मानित, शिक्षादूत पुरस्कार तीन शिक्षकों को प्रदान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के तहत आयोजित सम्मान समारोह में जिले के चार शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य, नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल थे। जिला स्तर के ज्ञानदीप पुरस्कार से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उदयपुर की शिक्षिका अंजली सरिता बड़ा को सम्मानित किया गया। उन्होंने स्थानीय संसाधनों से टीएलएम (टीचिंग लर्निंग मैटेरियल) तैयार कर खेल-खेल में पढ़ाई को प्रभावी बनाया।

साथ ही मूर्तिकला, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में रचनात्मकता विकसित की और उनसे आत्मीय जुड़ाव स्थापित किया। विकासखंड स्तर के शिक्षादूत पुरस्कार से प्रधान पाठक अनूप रंजन सोनी (प्राथमिक शाला बुले खास), शिक्षिका सावित्री प्रजापति तथा सहायक शिक्षक सलमोन केरकेट्टा (प्राथमिक शाला जरहाडांड़) को सम्मानित किया गया। अनूप रंजन सोनी ने व्यक्तिगत शिक्षण योजना और चित्र आधारित शिक्षण से कमजोर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार किया। सावित्री प्रजापति ने बालिकाओं की शिक्षा, लेखन-पठन और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। वहीं सलमोन केरकेट्टा ने

गणित को प्रयोगों के जरिए सरल बनाया, अंग्रेजी शब्दावली विकसित करने के लिए टीएलएम तैयार किए तथा बच्चों की छोटी-छोटी शैक्षणिक जरूरतें स्वयं के खर्च से पूरी कर मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष विकासखंड स्तर पर शिक्षादूत, जिला स्तर पर ज्ञानदीप तथा संभाग स्तर पर शिक्षाश्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में एमसीबी के होनहारों का कमाल

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीनों मेधावी छात्रों से घर पहुंचकर की मुलाकात, दी शुभकामनाएं

588 अंक | अनुराग नाथ त्रिपाठी
(खड़गवां)

611 अंक | आदित्य अग्रवाल
(मनेन्द्रगढ़)

537 अंक | मोहम्मद अयाज
(मनेन्द्रगढ़)

मेहनत, लगन और समर्पण की मिसाल बने हमारे युवा, आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में चमके एमसीबी के होनहार,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घर पहुंचकर किया सम्मानित

611 अंक लाने वाले आदित्य अग्रवाल, 588 अंक हासिल करने वाले अनुराग नाथ त्रिपाठी और 537 अंक प्राप्त करने वाले मोहम्मद अयाज़ को दी शुभकामनाएं,कहा... ऐसी प्रतिभाएं विकसित भारत की मजबूत नींव

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़/खड़गवां,25 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे जिले का गौरव बढ़ाया है, विद्यार्थियों की इस उल्लेखनीय सफलता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल स्वयं उनके घर पहुंचे और पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया,उन्होंने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया है कि निरंतर प्रयास और स्पष्ट लक्ष्य के साथ कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उपलब्धि केवल उनके परिवार की नहीं,बल्कि पूरे एमसीबी जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सभी विद्यार्थी भविष्य में कुशल एवं संवेदनशील चिकित्सक बनकर समाज और देश की सेवा करेंगे।

611 अंक प्राप्त करने वाले आदित्य अग्रवाल का किया सम्मान-स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ में अतुल अग्रवाल के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके सुपुत्र आदित्य अग्रवाल से सौजन्य भेंट की, आदित्य ने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में 611 अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है, इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आदित्य की मेहनत,लगन और प्रतिभा अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है,उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर आदित्य निश्चित रूप से समाज की सेवा करेंगे और देश, प्रदेश तथा अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे।

खड़गवां के अनुराग नाथ त्रिपाठी ने 588 अंक से बढ़ाया क्षेत्र का मान-इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री खड़गवां पहुंचे,जहां उन्होंने अनुराग नाथ त्रिपाठी को उनके निवास पर सम्मानित किया। अनुराग ने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में 588 अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है, स्वास्थ्य मंत्री ने अनुराग को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि पूरे खड़गवां क्षेत्र के लिए गौरव की बात है, उन्होंने कहा कि अनुराग ने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्होंने विश्वास जताया कि अनुराग भविष्य में एक कुशल एवं संवेदनशील चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करेंगे।

537 अंक हासिल करने वाले मोहम्मद अयाज़ को भी दी शुभकामनाएं-स्वास्थ्य मंत्री ने मनेन्द्रगढ़ में अब्दुल अज़ीज़ के निवास पहुंचकर उनके सुपुत्र मोहम्मद अयाज़ से भी मुलाकात की, अयाज़ ने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में 537 अंक प्राप्त कर अपने परिवार, क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है,इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है,उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मोहम्मद अयाज़ चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

प्रतिभाओं का सम्मान समाज को देता है सकारात्मक संदेश

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान करना समाज की जिम्मेदारी है,इससे अन्य विद्यार्थियों को भी कठिन परिश्रम,अनुशासन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है,उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है,प्रदेश के युवाओं की सफलता ही विकसित छत्तीसगढ़ की पहचान बनेगी।

परिजनों और क्षेत्रवासियों ने जताया हर्ष

आदित्य अग्रवाल,अनुराग नाथ त्रिपाठी और मोहम्मद अयाज़ की इस सफलता पर उनके परिजनों,शिक्षकों,मित्रों,शुभचिंतकों एवं क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं,सभी ने विश्वास जताया कि ये तीनों विद्यार्थी भविष्य में चिकित्सा सेवा के माध्यम से समाज की सेवा कर जिले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे।

खेत में जुताई के दौरान पलटा ट्रैक्टर,चालक की दबकर मौत

फंसे ट्रैक्टर को जबरन निकालने की कोशिश बनी हादसे की वजह,15 दिन में तीसरे चालक की गई जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के टिकरापारा गांव में शुक्रवार को खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे चालक का शव बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार टिकरापारा निवासी 26 वर्षीय सुरेंद्र तिग्गा खेत की जुताई कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर खेत में फंस गया। बताया जा रहा है कि चालक ट्रैक्टर को जबरन बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया और वह उसके नीचे दब गया। हादसे की सूचना मिलते ही कमलेश्वरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर हटाकर चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में पिछले 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर पलटने की यह तीसरी जानलेवा घटना है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने खेतों में सुरक्षा उपायों की अनदेखी और ट्रैक्टर संचालन में बरती जा रही लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन ने किसानों व ट्रैक्टर चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

खेलने निकला 15 वर्षीय छात्र जंगल में मृत मिला, हत्या की आशंका

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टिहरी के जंगल में 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक गुरुवार शाम घर से खेलने जाने की बात कहकर निकला था,लेकिन वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह जंगल में उसका शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम सलका निवासी विरेंद्र कंवर (15), पिता पिकेश्वर सिंह कंवर, कक्षा 9वीं का छात्र था। गुरुवार शाम वह खेलने की बात कहकर घर से निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह ग्राम टिहरी के जंगल में योग करने पहुंचे लोगों ने एक किशोर का शव देखा। इसकी सूचना सरपंच और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान विरेंद्र के रूप में की। सूचना पर उदयपुर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में मृतक के चेहरे पर खरोंच तथा पैर में घसीटे जाने जैसे निशान मिले हैं।

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग खिलाड़ियों ने कलेक्टर अजीत वसंत से की सौजन्य भेंट

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में 12 पदक जीतने पर कलेक्टर ने खिलाड़ियों को दी बधाई एवं शुभकामनाएं...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिले के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग खिलाड़ियों ने शनिवार को कलेक्टर श्री अजीत वसंत से सौजन्य भेंट कर हाल ही में आयोजित 25वीं छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्यस्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर श्री वसंत ने खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले को 12 पदक दिलाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, अनुशासन और मेहनत के बल पर सरगुजा जिले का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया है तथा आगामी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें। इस दौरान खिलाड़ियों ने जिले में शूटिंग खेल को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की मांग भी कलेक्टर के समक्ष रखी। इस अवसर पर शकील फिरदौसी,आसिफ अली,इरफान सिद्दीकी,जैनुल हसन फिरदौसी,अली हसन सिद्दीकी,अदीब सिद्दीकी, बंटी मंडल,शाहजाद खान,विशेष श्रीवास्तव,निशांत सिंह देव,अरुण खाखा,आलोक सिंह,अलकान फिरदौसी,शिबान फिरदौसी तथा अधिवक्ता संजय अम्बष्ट उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 25वीं छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्यस्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप में सरगुजा जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले को कुल 12 पदक दिलाए,जिनमें स्वर्ण,रजत एवं कांस्य पदक शामिल हैं।

भाजयुमो सरगुजा के नए जिला प्रभारी सन्नी केसरी का प्रथम नगर आगमन, संगठनात्मक बैठक में बनी आगामी रणनीति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) सरगुजा के नवनियुक्त जिला प्रभारी सन्नी केसरी के प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई,जिसमें आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसौदिया ने कहा कि युवा मोर्चा संगठन की सबसे सक्रिय इकाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिला प्रभारी सन्नी केसरी ने कहा कि युवा कार्यकर्ताओं की भागीदारी से ही संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को युवाओं एवं आमजन तक पहुंचाने तथा बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष निशांत सिंह सोलू ने बैठक की कार्ययोजना से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। बैठक में विशेष रूप से 'वन बूथ,20 यूथ' अभियान की रणनीति पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष, जिला उपाध्यक्ष विकास पांडेय, जन्मेजय मिश्रा सहित भाजयुमो के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नीट मामले पर विधायक भूलन मरावी का विपक्ष पर हमला...कहा-युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार उठा रही ठोस कदम,विपक्ष कर रहा राजनीति

-संवाददाता-
सूरजपुर,25 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार की पहल का समर्थन करते हुए कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' के दलों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है,उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर एवं प्रभावी कदम उठा रही है,जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। जारी बयान में विधायक भूलन सिंह मरावी ने कहा कि नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था, सख्त दंड और आवश्यक कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है, इससे स्पष्ट है कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने और मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, विधायक मरावी ने कहा कि केंद्र सरकार के सकारात्मक और समाधान आधारित दृष्टिकोण के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपना अनशन समाप्त किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार संवाद और समाधान की नीति पर आगे बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों और युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में पहल की है,उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' के दल छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर उनकी भावनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे,उनका कहना था कि विपक्ष का उद्देश्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि भ्रम और असंतोष का माहौल तैयार करना था, भूलन सिंह मरावी ने कहा कि देश का युवा वर्ग जागरूक है।

78 साल बाद भी नहीं पहुंची विकास की रोशनी

धुमड़ाड आज भी पक्की सड़क को तरस रहा

बरसात में दलदल बनी सड़क, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती | बच्चे कीचड़ पार कर जाते हैं स्कूल

कई सरपंच, विधायक और सांसद बदले, सरकारें बदलीं; लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी इंतजार अधूरा

सरकारें बदलीं...जनप्रतिनिधि बदले,लेकिन धुमड़ाड आज भी पक्की सड़क से वंचित

वोट हर चुनाव में,सड़क आज तक नहीं,78 साल बाद भी धुमड़ाड की बदहाल तस्वीर...

अविभाजित मध्यप्रदेश के दौर की पंचायत,लेकिन धुमड़ाड आज भी पक्की सड़क को तरस रहा...

धुमड़ाड की पीड़ा,लोकतंत्र के हर चुनाव में भागीदारी,फिर भी पक्की सड़क का सपना अधूरा

अविभाजित मध्यप्रदेश और सरगुजा के दौर से अस्तित्व में है ग्राम पंचायत,न जाने कितने सरपंच,विधायक और सांसद बदले,लेकिन आज भी कीचड़ में घिसट रही जिंदगी...

चुनाव में वोट चाहिए,लेकिन सड़क नहीं,बरसात में कट जाता है गांव, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, बच्चे कीचड़ पार कर जाते हैं स्कूल

रवि सिंह

कोरिया/सोनहत,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, देश अमृतकाल का जश्न मना रहा है,सरकारें 'विकसित भारत','ग्रामीण विकास','हर गांव तक सड़क','सबका साथ-सबका विकास' और 'अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ' जैसे दावे कर रही हैं,लेकिन कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चकडाड़ के आश्रित ग्राम धुमड़ाड की जमीनी हकीकत इन दावों की परतें उधेड़ देती है,यह कोई नया बसा गांव नहीं है,यह उस दौर का गांव है,जब न कोरिया जिला बना था और न ही प्रदेश का विभाजन हुआ था,अविभाजित मध्यप्रदेश और अविभाजित सरगुजा जिले के समय से अस्तित्व में रहे इस ग्राम पंचायत ने लोकतंत्र के हर पड़ाव को देखा है,न जाने कितने पंचायत चुनाव हुए,कितने सरपंच बने, कितने जनपद और जिला पंचायत सदस्य बदले, कितने विधायक और सांसद जनता ने चुने, कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन इन 78 वर्षों में यदि कुछ नहीं बदला, तो वह है धुमड़ाड की सड़क,आज भी इस गांव के लोग यह सवाल पूछने को मजबूर हैं कि आखिर लोकतंत्र में उनकी भूमिका केवल वोट डालने तक ही सीमित क्यों रह गई? बता दे की कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चकडाड़ के आश्रित ग्राम धुमड़ाड की कहानी विकास के उन दावों पर सवाल खड़ी करती है,जिनमें हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाती है,यह कोई नया गांव नहीं,बल्कि अविभाजित मध्यप्रदेश और अविभाजित सरगुजा जिले के समय से अस्तित्व में रही एक पुरानी ग्राम पंचायत का हिस्सा है,इतने लंबे समय में न जाने कितने पंचायत चुनाव हुए,कई सरपंच चुने गए, जनपद और जिला पंचायत प्रतिनिधि बदले, विधायक और सांसद भी बदलते रहे,लेकिन धुमड़ाड आज भी एक पक्की सड़क के लिए तरस रहा है,ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी बरसात के दिनों में गांव का संपर्क लगभग टूट जाता है,सड़क की जगह कीचड़ और दलदल नजर आता है,ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब इतने वर्षों में सरकारें और जनप्रतिनिधि बदलते रहे, तो आखिर धुमड़ाड तक विकास की सबसे बुनियादी सुविधा–पक्की सड़क–क्यों नहीं पहुंच सकी?

हर चुनाव में वादे,हर चुनाव के बाद खामोशी-ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आते ही नेताओं के वाहन गांव तक पहुंच जाते हैं, विकास के वादे किए जाते हैं,सड़क बनाने के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही गांव फिर उसी बदहाल सड़क और उपेक्षा के भरोसे छोड़ दिया जाता है,एक ग्रामीण की पीड़ा व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करती है नेता वोट मांगने आते हैं,सड़क बनाने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई वापस नहीं आता। हम हर बार भरोसा करते हैं और हर बार ठगे जाते हैं।

मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी बेअसर- लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर मतदान बहिष्कार तक का निर्णय लिया था,बाद में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन पर उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास दिखाते हुए मतदान किया,लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद न सड़क बनी और न ही कोई ठोस पहल दिखाई दी,अब ग्रामीणों का सवाल है कि यदि आश्वासन केवल मतदान कराने के लिए थे, तो फिर जनता का विश्वास कौन लौटाएगा?

78 वर्षों में आखिर जवाबदेह कौन?- यह सवाल केवल वर्तमान सरकार से नहीं,बल्कि उन सभी जनप्रतिनिधियों से है जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, आखिर क्यों धुमड़ाड जैसी पुरानी पंचायत आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है? जब करोड़ों रुपये की विकास योजनाएं स्वीकृत होती हैं, ग्रामीण सड़क योजनाएं संचालित होती हैं और पंचायतों को विकास मद में राशि मिलती है, तो फिर धुमड़ाड तक उसका लाभ क्यों नहीं पहुंचा? यदि यह प्रशासनिक विफलता है तो जिम्मेदार कौन है? यदि यह राजनीतिक उपेक्षा है तो उसका जवाब कौन देगा?

क्या विकास के नक्शे में धुमड़ाड का नाम ही नहीं है?

प्रदेश और देश में विकास की तस्वीरें दिखाई जाती हैं,करोड़ों की लागत से सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस-वे,फ्लाईओवर और स्मार्ट सिटी की चर्चा होती है,लेकिन धुमड़ाड तक पहुंचने वाली सड़क आज भी इस बात की गवाही देती है कि विकास के सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच कितना बड़ा अंतर है,बरसात शुरू होते ही गांव की सड़क सड़क नहीं रहती,बल्कि दलदल में बदल जाती है,जगह-जगह गहरे गड्ढे कीचड़ और पानी का जमाव ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि मानो यह सड़क नहीं,किसी उपेक्षित जंगल का रास्ता हो, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है,दोपहिया वाहन फिसलकर गिर जाते हैं और चारपहिया वाहन गांव तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाते,सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस गांव का अस्तित्व केवल चुनाव के समय ही याद आता है?

सड़क नहीं,मौत का रास्ता बन चुका है यह मार्ग...

धुमड़ाड की बदहाल सड़क केवल असुविधा नहीं है,बल्कि यह लोगों की जान पर भी भारी पड़ रही है,ग्रामीण बताते हैं कि बरसात में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती,गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना किसी परीक्षा से कम नहीं होता,गंभीर मरीजों और बुजुर्गों को चारपाई या खाट पर उठाकर कई किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है,स्वास्थ्य सेवाओं की बात करने वाली व्यवस्था से ग्रामीण पूछ रहे हैं कि यदि मरीज अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाएगा,तो स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आखिर किसे मिलेगा?

बच्चों का भविष्य भी कीचड़ में फंस रहा है...

धुमड़ाड के बच्चे हर दिन कीचड़ और दलदल से जूझते हुए स्कूल पहुंचते हैं,बरसात में कई बच्चे रास्ते में फिसल जाते हैं,उनकी किताबें और स्कूल ड्रेस खराब हो जाती हैं,कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंच पाते,सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है,लेकिन धुमड़ाड के अभिभावक पूछ रहे हैं कि क्या सुरक्षित सड़क भी शिक्षा के अधिकार का हिस्सा नहीं होनी चाहिए?

ग्रामीणों की मांग...अब केवल आश्वासन नहीं...सड़क चाहिए...

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल गांव का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए,पक्की सड़क निर्माण की स्वीकृति दी जाए तथा पंचायत क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और खर्च की निष्पक्ष जांच कराई जाए,ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस बार भी उनकी वर्षों पुरानी मांगों की अनदेखी की गई तो वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

अब सवाल जनता का नहीं, व्यवस्था की जवाबदेही का है...

धुमड़ाड केवल एक गांव नहीं,बल्कि उन तमाम ग्रामीण इलाकों का प्रतीक है जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समान विकास अब भी अधूरी है। जिस गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती,जहां बच्चे कीचड़ में स्कूल जाने को मजबूर हों और जहां बरसात में पूरा गांव दुनिया से कट जाए,वहां विकास के दावे स्वतः कठघरे में खड़े हो जाते हैं,आज़ादी के 78 वर्ष बाद धुमड़ाड पूछ रहा है क्या हमारे हिस्से में केवल वोट देने का अधिकार है,या फिर सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी इस लोकतंत्र में कभी मिलेगा?

बिना चारा,पानी और छाया के गौवंश गौठान में बंद!

क्या केवल आदेश जारी कर जिम्मेदारी पूरी मान रहा प्रशासन?

चेरवापारा-मुरमा रोड स्थित पुराने गौठान में चार दिनों से सैकड़ों गौवंश होने का दावा...

बैकुंठपुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र स्थित चेरवापारा-मुरमा रोड के पुराने गौठान को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं,गौ सेवक अनुराग दुबे का आरोप है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गठित समिति द्वारा सैकड़ों गौवंशों को पिछले चार दिनों से पुराने गौठान में रखा गया है, लेकिन वहां उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आरोप है कि गौठान में न तो पर्याप्त शेड (छाया) की व्यवस्था है, न चारा और भूसे की,न पीने के पानी की समुचित सुविधा है और न ही बिजली की व्यवस्था,साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि गौवंशों की देखरेख के लिए नियमित रूप से कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है,जिसके कारण पशु भूख-प्यास से परेशान हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन गौवंशों को गौठानों में रखने का निर्णय लेता है, तो सबसे पहले वहां आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए,उनका कहना है कि बिना तैयारी के बड़ी संख्या में गौवंशों को एक स्थान पर रखने से उनकी देखभाल प्रभावित हो सकती है, ग्रामीणों ने यह भी चिंता जताई है कि यदि किसी गौवंश की मृत्यु होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी,उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गौठानों में पर्याप्त शेड, चारा,पानी,प्रकाश व्यवस्था और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के बाद ही वहां गौवंशों को रखा जाए।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें...

गौठान में पर्याप्त शेड एवं छाया की व्यवस्था, नियमित चारा,भूसा एवं पानी की उपलब्धता,गौवंशों की देखभाल के लिए कर्मचारियों की तैनाती, बिजली एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, गौठानों का नियमित निरीक्षण और निगरानी।

नगरपालिका की जनसमस्याओं को लेकर 26 जुलाई को होगा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन

नेता प्रतिपक्ष लालमुनी यादव ने प्रशासन को दी सूचना,पेयजल,सड़क,सफाई,स्ट्रीट लाइट और कथित भ्रष्टाचार समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर राजीव चौक में होगा आंदोलन

-संवाददाता-

शिवपुर-चरचा/कोरिया, 25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। शिवपुर-चरचा नगर पालिका क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर नगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनी यादव ने 26 जुलाई को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का ऐलान किया है, इस संबंध में उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर को विधिवत पत्र सौंपकर आंदोलन की सूचना दी है,प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन रविवार 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक राजीव गांधी चौक,शिवपुर-चरचा में आयोजित किया जाएगा, जारी सूचना के अनुसार,यह आंदोलन नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई मूलभूत नागरिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर किया जा रहा है,नेता प्रतिपक्ष ने नगरवासियों से भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है।

आठ सूत्रीय मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन

अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए पत्र में नगर पालिका की कार्यप्रणाली और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है,इनमें सबसे प्रमुख समस्या पेयजल संकट को बताया गया है,जिसे पत्र में 'विकराल रूप' धारण कर चुकी समस्या बताया गया है,इसके अलावा मुख्य मार्गों और विभिन्न वार्डों में स्ट्रीट लाइट की खराब व्यवस्था,जर्जर सड़कें, नालियों की समस्या,सफाई व्यवस्था में कथित लापरवाही, वार्डों में नियमित फॉगिंग एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होना,नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं होने जैसे मुद्दों को भी आंदोलन का आधार बनाया गया है,नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ये सभी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनके समाधान के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

पेयजल और सफाई व्यवस्था बनी प्रमुख चिंता

धरना-प्रदर्शन की प्रस्तावित मांगों में पेयजल संकट को सबसे गंभीर समस्या बताया गया है,आरोप है कि कई वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रभावित है,जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है,इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि कई क्षेत्रों में नियमित सफाई नहीं होने और फॉगिंग व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं होने से नागरिकों में संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है, बरसात के मौसम में यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है।

सड़क,नाली और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर भी सवाल...

आंदोलन की प्रमुख मांगों में नगर पालिका क्षेत्र की सड़क,नाली और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को भी शामिल किया गया है,पत्र में आरोप लगाया गया है कि मुख्य मार्गों के अलावा कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं,जिससे रात के समय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है,इसी प्रकार कई स्थानों पर सड़क और नालियों की खराब स्थिति के कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,बरसात के दौरान जलभराव और कीचड़ की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं।

कथित भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के वेतन का भी उठाया मुद्दा...

नेता प्रतिपक्ष लालमुनी यादव ने नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है,पत्र में इस संबंध में जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है,इसके साथ ही नगर पालिका कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से शामिल किया गया है,उनका कहना है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनका मनोबल प्रभावित होता है और इसका असर नगर पालिका की सेवाओं पर भी पड़ता है।

प्रशासन को पहले ही दी गई आंदोलन की सूचना

धरना-प्रदर्शन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को विधिवत सूचना पत्र सौंपा गया है,इसकी प्रतिलिपि थाना प्रभारी चरचा तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, शिवपुर-चरचा को भी भेजी गई है,इससे स्पष्ट है कि आंदोलन की पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक नियमों के तहत अपनाई गई है,जारी पोस्टर में भी नगरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में शामिल होने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की गई है,पोस्टर में 'आपकी समस्या,हमारी आवाज' और 'एकजुट होकर आवाज उठाएं' जैसे संदेश भी दिए गए हैं।

अब नगर पालिका प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर...

26 जुलाई को प्रस्तावित इस एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन को लेकर अब नगर पालिका प्रशासन की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी,यदि आंदोलन से पहले प्रशासन मांगों पर सकारात्मक पहल करता है तो स्थिति बदल सकती है,अन्यथा नगरवासियों की भागीदारी के साथ यह प्रदर्शन स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण जनआंदोलन का रूप ले सकता है, फिलहाल नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल,सड़क, नाली,स्ट्रीट लाइट,सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों के वेतन जैसे मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं,अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन मांगों के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है और 26 जुलाई को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन का स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

आईसी मार्ट आत्महत्या प्रकरण में नया मोड़

बैद परिवार की पहली प्रतिक्रिया!

'हमने FIR नहीं कराई, समझौते से मामला समाप्त हुआ था'

पुलिस पर गंभीर आरोप

आईसी मार्ट प्रकरण में बैद परिवार की पहली प्रतिक्रिया...

कहा...निष्पक्ष जांच हो,पूरे परिवार को बनाया जा रहा निशाना

आईसी मार्ट प्रकरण में बैद परिवार का बड़ा पलटवार...एएसआई अलंगो दास की भूमिका की भी हो जांच,हमें नहीं पूरे परिवार को बनाया जा रहा निशाना...

आईसी मार्ट प्रकरण में बैद परिवार ने तोड़ी चुप्पी,पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का लगाया आरोप...

आत्महत्या दुःखद,लेकिन जांच एकतरफा नहीं हो...बैद परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल...

आरोपी परिवार ने खोला मोर्चा,कहा... महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा, निष्पक्ष जांच कराए प्रशासन

आईसी मार्ट प्रकरण में बैद परिवार का बड़ा दावा,हमें नहीं,एएसआई की भूमिका की भी हो जांव...

- रवि सिंह-

बैकुंठपुर,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बहुचर्चित आईसी मार्ट आत्महत्या प्रकरण में अब एक नया मोड़ सामने आया है,अब तक पुलिस की कार्रवाई और मृत छात्रा के परिजनों की ओर से उठ रही मांगों के बीच आरोपी बनाए गए बैद परिवार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा है,परिवार ने विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि पूरे मामले में उन्हें एकतरफा तरीके से आरोपी बनाया जा रहा है,जबकि घटना के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है,परिवार का कहना है कि वे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं,लेकिन जांच निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने पुलिस पर महिलाओं,युवतियों और बुजुर्गों को परेशान करने, बैंक खाते सीज करने तथा पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, इन आरोपों पर समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

एएसआई अलंगो दास की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो...

बैद परिवार का कहना है कि पूरे प्रकरण में केवल आईसी मार्ट संचालकों की भूमिका की जांच की जा रही है,जबकि बैकुंठपुर सिटी कोतवाली में पदस्थ एएसआई अलंगो दास की भूमिका की भी निष्पक्ष जाच होनी चाहिए,परिवार का दावा है कि चोरी की घटना के बाद एएसआई अलंगो दास स्वयं मृतका की ओर से बातचीत करने आईसी मार्ट पहुचे थे, उस दौरान उन्होंने कथित रूप से मृतका के सामने यह कहा था कि यदि चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस तक पहुंच गया तो जेल जाना तय है,बैद परिवार का आरोप है कि यदि मृतका के मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न हुआ, तो उस पहलू की भी जांच होनी चाहिए,परिवार का यह भी दावा है कि उनकी ओर से मृतका को न तो डराया गया और न ही किसी प्रकार की धमकी दी गई,उनका आरोप है कि जांच एजेंसी इस पहलू की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है,बैद परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि एएसआई अलंगो दास बाद में स्वयं को मृतका के रिश्तेदार के रूप में प्रकरण से जोड़ते हुए सामने आए,जबकि उनकी भूमिका और घटनास्थल पर उनके पहुंचने की परिस्थितियों की भी जांच की जानी चाहिए,परिवार ने मांग की है कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि एएसआई अलंगो दास किस हैसियत से आईसी मार्ट पहुंचे थे, उनकी उस समय की भूमिका क्या थी तथा क्या उनके कथित व्यवहार का मृतका की मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा,परिवार का कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ जांच आवश्यक है।

चोरी की घटना से शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम-बैद परिवार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पूरे मामले की शुरुआत आईसी मार्ट में हुई कथित चोरी की घटना से हुई,परिवार का दावा है कि 7 जुलाई 2026 को मृतक छात्रा अपनी 15 वर्षीय छोटी बहन के साथ आईसी मार्ट में कथित रूप से चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं,परिवार के अनुसार पूछताछ के दौरान मृतक छात्रा ने कथित रूप से चोरी स्वीकार की तथा ले जाए गए सामान की सूची भी तैयार कर दी थी,इसके बाद उससे कहा गया कि वह अपने परिजनों को बुलाए,बताया गया है कि मृतक छात्रा अपनी स्कूटी वहीं छोड़कर घर चली गई और कुछ समय बाद अपने परिचित अलंगो दास, जो पुलिस विभाग में कार्यरत बताए गए हैं,के साथ वापस आई।

'हमारा उद्देश्य एफआईआर नहीं, बच्चों को सुधारना था'- प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उस समय आईसी मार्ट प्रबंधन का उद्देश्य किसी किशोरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करना नहीं था,परिवार का दावा है कि एएसआई अलंगो दास ने बातचीत के दौरान कहा कि यदि चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास पहुंच गया तो जेल जाना तय है,यह बातचीत मृतक छात्रा भी सुन रही थी, बैद परिवार के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनका उद्देश्य किसी बच्चे को जेल भेजना नहीं बल्कि उसे ऐसी गलती दोबारा न करने के लिए समझाना है,चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 20 हजार रुपये बताई गई और उसी राशि की भरपाई पर सहमति बनने के बाद मामला लगभग समाप्त मान लिया गया।

अगले दिन पिता पहुंचे,सीसीटीवी देखने के बाद मामला खत्म करने की बात-प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगले दिन मृतक छात्रा के पिता,जो स्वयं पुलिस विभाग में कार्यरत बताए गए हैं,आईसी मार्ट पहुंचे,परिवार का दावा है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद चोरी की घटना स्वीकार की,इसके बाद आईसी मार्ट प्रबंधन ने उनसे कहा कि वे उचित समझें वैसा निर्णय लें और यदि कोई सामान घर पर हो तो लौटा दें,वैद परिवार का कहना है कि इसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं कराई और मामला वहीं समाप्त मान लिया।

आत्महत्या के बाद अचानक बदल गया पूरा घटनाक्रम

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगले दिन,8 जुलाई को छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली,परिवार ने इस घटना को अत्यंत दुःखद बताते हुए मृत छात्रा के प्रति संवेदना व्यक्त की है, हालांकि परिवार का कहना है कि आत्महत्या के बाद पूरे मामले की दिशा अचानक बदल गई और बिना सभी परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच किए आईसी मार्ट संचालकों को आरोपी बना दिया गया।

आत्महत्या के सभी कारणों की जांच हो...

बैद परिवार का कहना है कि आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामले में केवल एक ही कोण से जांच नहीं होनी चाहिए,परिवार ने दावा किया है कि घटना से पहले कथित रूप से मृतक छात्रा के सामने जेल जाने की बात कही गई थी और जांच में इस पहलू की भी पड़ताल होनी चाहिए कि उसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ा, परिवार का कहना है कि किसी एक पक्ष को पहले से दोषी मानकर विवेचना करना न्यायसंगत नहीं होगा।

एफआईआर को बताया एकतरफा कार्रवाई-घटना के बाद बैकुंठपुर सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज किया गया,जिसमें आईसी मार्ट संचालक विनोद बैद,उनके बड़े भाई जगत वैद तथा अधिवक्ता दीपक वैद को आरोपी बनाया गया, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि विनोद वैद ने कानून का सम्मान करते हुए गिरफ्तारी दे दी है,लेकिन अन्य परिजनों को भी आरोपी बनाकर कार्रवाई की जा रही है,परिवार का आरोप है कि उपलब्ध तथ्यों की निष्पक्ष जांच किए बिना पूरे परिवार को संदेह के घेरे में लाया गया है।

महिलाओं और बच्चों को भी बनाया जा रहा दबाव का माध्यम-वैद परिवार ने सबसे गंभीर आरोप पुलिस कार्रवाई के तरीके पर लगाए हैं,प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि घटना के बाद से महिलाओं,युवतियों और अन्य निर्दोष परिजनों को बार-बार थाने बुलाया जा रहा है,परिवार का दावा है कि कई-कई घंटों तक उन्हें थाने में बैठाया जाता है,जिससे पूरा परिवार मानसिक तनाव में है,परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।

बैंक खाते सीज कर दिए गए,व्यापार पूरी तरह ठप्प-परिवार का कहना है कि घटना के बाद आईसी मार्ट पूरी तरह बंद पड़ा है, उनका दावा है कि बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है,जिससे व्यापार के साथ-साथ परिवार का दैनिक जीवन भी प्रभावित हो गया है,परिवार का कहना है कि यदि जांच चल रही है तो वह कानून के अनुसार चले,लेकिन पूरे परिवार की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सुरक्षा भी दी जाए-बैद परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि आईसी मार्ट और पूरे परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए,परिवार का कहना है कि घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण है और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस सुरक्षा आवश्यक है,साथ ही आईसी मार्ट को सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुनः खुलवाने की भी मांग की गई है।

परिवार ने रखीं कई प्रमुख मांगें, प्रेस विज्ञप्ति में वैद परिवार ने प्रशासन के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं—

- अपराध क्रमांक 214/2026 की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- पर्याप्त साक्ष्य के बिना अन्य परिजनों की गिरफ्तारी न की जाए।
- महिलाओं,युवतियों और निर्दोष परिवारजनों को परेशान करना बंद किया जाए।
- आत्महत्या के सभी संभावित कारणों की निष्पक्ष जांच हो।
- यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
- आईसी मार्ट एवं वैद परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।
- सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रतिष्ठान को पुनः संचालित करने की अनुमति दी जाए।

न्यायपालिका पर भरोसा,निष्पक्ष जांच की अपेक्षा-प्रेस विज्ञप्ति के अंत में वैद परिवार ने कहा है कि उन्हें भारतीय संविधान और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, परिवार ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग देगा और कानून की प्रक्रिया का सम्मान करेगा, साथ ही उन्होंने अपील की है कि मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच की जाए।

पुलिस का पक्ष आना अभी शेष

यह उल्लेखनीय है कि इस समाचार में वर्णित अनेक बातें वैद परिवार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में किए गए दावे और आरोप हैं, इनकी सत्यता की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी,समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की गई थी,ऐसे में मामले के सभी पक्षों को सामने लाकर निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही आगे की स्थिति स्पष्ट करेगी।

पेपर लीक पर केंद्र सरकार सख्त,दोषियों को नहीं मिलेगी कोई राहत: चंपा देवी पावले

भाजपा जिलाध्यक्ष बोलीं...परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मनेन्द्रगढ़,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी एमसीबी की जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले ने कहा है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी,निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है, उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा ऐसे मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जारी बयान में श्रीमती पावले ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना और युवाओं के भविष्य की रक्षा करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों और प्रभावी व्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी राजनीतिक दल छात्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के बजाय इस मुद्दे पर भ्रम और अव्यवस्था का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कहना था कि विपक्ष ने छात्रों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, जबकि केंद्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेकर कठोर कानून और प्रभावी कार्रवाई की दिशा में पहल की है, श्रीमती पावले ने कहा कि सरकार द्वारा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था, दोषियों के लिए कड़ी सजा तथा अनियमितताओं में शामिल संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि इन उपायों से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा मेहनत करने वाले छात्रों का विश्वास और मजबूत होगा,उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग जागरूक है और वह अच्छी तरह समझता है कि कौन उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है और कौन केवल राजनीतिक लाभ के लिए आंदोलन और भ्रम की राजनीति कर रहा है।

पीएम मोदी के फैसलों और सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने से विपक्ष का एजेंडा बेनकाब : देवेन्द्र तिवारी

भाजपा जिलाध्यक्ष बोले-सरकार ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाए निर्णायक कदम,विपक्ष केवल भ्रम और राजनीति फैलाने में जुटा

कोरिया,25 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीट पेपर लीक प्रकरण में कड़े कदम उठाए जाने तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपना अनशन समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है, उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों से विपक्ष का वास्तविक राजनीतिक चरित्र और उसका कथित 'भारत विरोधी एजेंडा' पूरी तरह उजागर हो गया है। जारी बयान में देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित एवं निर्णायक कदम उठाने का निर्णय लिया है,उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था, दोषियों के लिए 5 से 10 वर्ष तक की सजा, कड़ी जमानत शर्तों तथा अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वाले कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधानों की दिशा में पहल की है, भाजपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख और संवेदनशील पहल के बाद केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने भी सरकार पर भरोसा जताते हुए अपना अनशन समाप्त कर दिया। उनके अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, देवेन्द्र तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' के अन्य दलों का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालना नहीं था, बल्कि छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाकर देश में भ्रम, असंतोष और अराजकता का माहौल तैयार करना था, उन्होंने कहा कि जब सरकार ने समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए, तब विपक्ष की राजनीति स्वतः बेनकाब हो गई, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस निर्णय ले रहा है और कौन केवल उनके नाम पर राजनीति कर रहा है, भाजपा सरकार का संकल्प है कि मेहनत और प्रतिभा के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले प्रत्येक छात्र के अधिकारों की रक्षा की जाए तथा परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से रोका जाए, भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था स्थापित करना है,जिसमें पारदर्शिता,निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हो,उन्होंने दोहराया कि पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर ने क्यों फिल्में करना कर दिया था बंद?

करिश्मा कपूर के गोविंदा के साथ काम न करने को लेकर उनकी को-स्टार ने बात की है। साथ ही कहा है कि एक्ट्रेस में काफी एटीट्यूड था।

गोविंदा और करिश्मा कपूर कभी फिल्मी दुनिया की हिट जोड़ियों में गिने जाते थे। इसी दौरान उनका नाम भी जुड़ा। फिर एक दिन उनकी साथ में फिल्में आनी बंद हो गईं। अब सालों बाद करिश्मा और गोविंदा की को-स्टार रह चुकीं एक्ट्रेस ने उनके साथ में काम न करने पर बात की है।

यह को-स्टार हैं शगुफ्ता अली जिन्होंने करिश्मा कपूर और गोविंदा के साथ फिल्म हीरो नंबर 1 में काम किया था। सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि करिश्मा ने गोविंदा संग काम करना क्यों बंद कर दिया,तब उन्होंने रिएक्शन दिया।

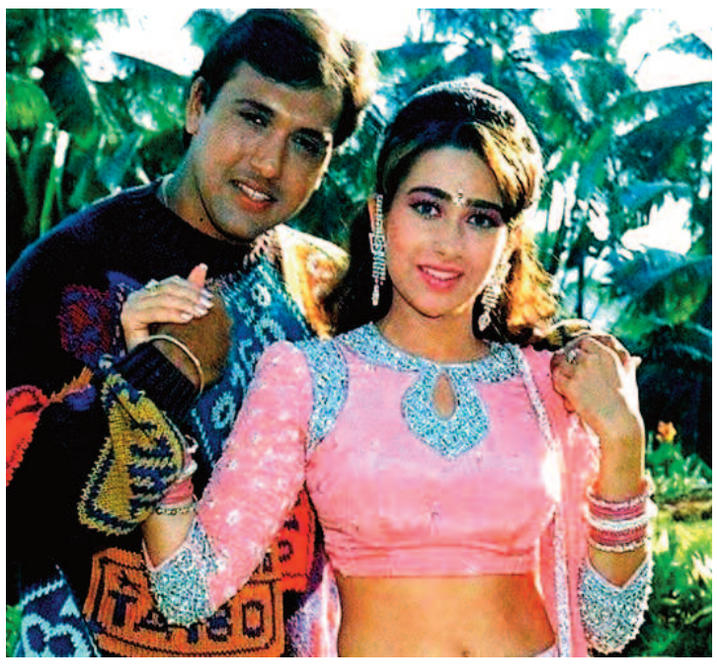

क्यों गोविंदा संग फिल्में नहीं करती थीं करिश्मा?

शगुफ्ता अली ने बताया कि करिश्मा मेहनती और टैलेंटेड तो थीं,लेकिन उनमें बहुत एटीट्यूड था। उन्होंने कहा कि शायद करिश्मा की गोविंदा संग काम करने की दिलचस्पी खत्म हो गई होगी। उन्होंने कहा...दिलचस्पी खत्म हो गया होगा। प्यार मोहब्बत खत्म हो गया होगा। हीरोइंस के मूड का भी क्या भरोसा है। और बहुत ज्यादा एंबीशियस होना भी अच्छा नहीं है। करिश्मा ओवर-एंबीशियस थीं। वह बहुत मेहनती थीं,लेकिन एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा था।

सेट पर सही नहीं था करिश्मा का बर्ताव?

शगुफ्ता अली ने आगे कहा,सेट पर आपका रवैया और आपके बर्ताव से भी फर्क पड़ता है। अगर कोई आपका को-एक्टर है,तो तालमेल होना जरूरी है। चाहे आप साथ में कोई सीन कर रहे हों या इंटरव्यू दे रहे हों, दोनों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। इससे हमारी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। अगर मैं आपको क्यू देने के लिए सेट पर मौजूद हूं तो आपको भी मेरे लिए वहां होना चाहिए। या फिर न भी हों,तो भी मैं बिना क्यू के सीन कर सकती हूं। इसी तरह मैं 40 सालों से इस इंडस्ट्री में टिकी हुई हूं।

भोजपुरी बवाल में काजल राघवानी का सवाल,आम्रपाली ने दिया जवाब

भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों से सजा नया शो भोजपुरी बवाल शुरुआत से ही चर्चा में आ गया है। इस शो में भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े नाम एक साथ नजर आ रहे हैं,जिनमें आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव (निरहुआ),काजल राघवानी, पवन सिंह और बिहार के नेता तेज प्रताप यादव शामिल हैं। शो के शुरुआती एपिसोड में ही कलाकारों के बीच हुई बातचीत ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच बहस होती दिखाई दे रही है। वीडियो में दोनों अभिनेत्रियां इंडस्ट्री में अपनी जगह, काम और लोकप्रियता को लेकर अपनी-अपनी बात रखती नजर आ रही हैं।

खुद को बिहार का ब्रैड पिट कहने वाले रवि किशन का सेंसरशिप पर बड़ा बयान, सतलुज विवाद पर कही यह बात

रवि किशन ने फिल्मों में सेंसरशिप को जरूरी बताया, खासकर मिर्जापुर: द मूवी के लिए,समाज के प्रति जवाबदेही पर जोर दिया...उन्होंने सतलुज फिल्म विवाद पर भी बात की और खुद को बिहार का ब्रैड पिट बताया...

सतलुज विवाद के बीच, रवि किशन ने फिल्मों में सेंसरशिप को लेकर अपनी बात रखी है। इस पर बोलते हुए रवि किशन ने कहा कि मिर्जापुर की रिलीज से पहले सेंसरशिप जरूरी है क्योंकि हमें समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए क्योंकि इसका असर युवाओं पर पड़ता है।

रवि ने खुद को बताया बिहार का ब्रैड पिट

एक्टर-नेता रवि किशन का फिल्मी करियर तीन दशक लंबा रहा है। रवि बताते हैं कि उन्हें नेशनल क्रश और बिहार का ब्रैड पिट कहा जाता है। हाल ही में रवि से दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज से जुड़ी सेंसरशिप की दिक्कतों के बारे में पूछा गया। इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिला था और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के दो दिन बाद ही इसे हटा दिया गया था। रवि खुद को सिनेमा का इनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। जब रवि से पूछा गया कि अगर सीबीएफसी उनके किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगाती तो उन्हें कैसा लगता। सतलुज के बारे में जवाब देते हुए रवि ने कहा कि जरूर कोई संवेदनशीलता का मुद्दा रहा होगा। उन्होंने इस मामले से खुद को अलग रखते हुए कहा, मुझे इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि फिल्म आई और हटा दी गई। सच कहूं तो,मुझे इसकी डिटेल नहीं पता।

एक्टर की आने वाली फिल्में

रवि किशन ने कहा कि एक एक्टर को फिल्म बनाते समय इन सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए कि एंटरटेनिंग फिल्म बनाने के चक्कर में कहीं वो अनजाने में किसी समुदाय को ठेस न पहुंचाएं। रवि किशन की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो एक्टर बहुत जल्द मिर्जापुर- द मूवी में नजर आएंगे। ये अमेजन प्राइम की पॉपुलर सीरीज है जिसे अब फिल्म में तब्दील किया जा रहा है। मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पाकिस्तानी स्टार्स युमना जैदी और बिलाल अब्बास खान के नए रोमांस की खबरें तेज

पाकिस्तानी एक्टर बिलाल अब्बास खान और युमना ज़ैदी के बहुत सारे फ़ैन हैं और वे इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक हैं। इस जोड़ी ने 2020 की हिट रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा प्यार के सदके में अब्दुल्ला और महज़बीन के किरदारों से लाखों लोगों का दिल जीता था। ड्रामा खत्म होने के सालों बाद भी, फ़ैन्स उनकी केमिस्ट्री पर प्यार बरसाते रहते हैं और बेसब्री से उनके दोबारा साथ आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसी अफ़वाहें चल रही हैं कि बिलाल और युमना छह साल बाद फिर से साथ काम करने वाले हैं। इस अटकल ने फ़ैन्स को उत्साहित कर दिया है, और कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह पसंदीदा जोड़ी एक और यादगार लव स्टोरी में वापसी करेगी। क्या बिलाल अब्बास खान और युमना ज़ैदी लैला मजनू में मुख्य भूमिका निभाएंगे? चल रही खबरों के अनुसार,आने वाले पाकिस्तानी ड्रामा लैला मजनू की कास्टिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शुजा असद और सजल अली अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं,और उनकी जगह बिलाल अब्बास खान और युमना ज़ैदी को मुख्य जोड़ी के तौर पर लेने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कास्टिंग के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन फ़ैन्स बिलाल और युमना को स्क्रीन पर फिर से साथ देखने की संभावना को लेकर अपना उत्साह ज़ाहिर कर रहे हैं। इस बीच, युमना ज़ैदी आखिरी बार देख ज़रा प्यार से में नज़र आई थीं। उम्मीद है कि वह अगली बार कैफ़े फ़िराक़ में अहद रज़ा मीर के साथ काम करेंगी;खबरों के मुताबिक,इस ड्रामा की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। दूसरी ओर, बिलाल अब्बास खान अपने पिछले ड्रामा मेरी जिंदगी है तू के बाद से लाइमलाइट से दूर रहे हैं और उन्होंने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

खेल समाचार

लगातार सीरीज हार के बाद जीता भारत

हरारे,25 जुलाई 2026। लगातार 2 टी20 सीरीज हारने के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कम से कम इस फॉर्मेट तो अच्छी खबर सामने आई है। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के 3 मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 90 रन से हरा दिया। पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम ने अब इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसी के साथ टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली टी20 सीरीज जीतने में कामयाब रही है।

बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का कमाल

जिम्बाब्वे की टीम भारतीय गेंदबाजों के घातक प्रदर्शन के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गई और 17.5 ओवरों में 129 रनों पर ऑलआउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए ओपनिंग बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 19 गेंदों में 32 रन (3 चौके, 3 छक्के) बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि तादिवानाशे मरुमानी ने 24 और रयान बर्ल ने 20 रनों का योगदान दिया। इनके

अलावा ब्रैड इवांस ने 19 रन बनाए, लेकिन कप्तान सिकंदर रज़ा (0) समेत टीम का मध्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाता रहा।

अभिषेक शर्मा ने झटके 3 विकेट

भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर शिकंजा कसे रखा और जिम्बाब्वे के किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया। ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2.5 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके। डेब्यू कर रहे यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट हासिल किए। उनके अलावा रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को 1-1 सफलता मिली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को बेहद सस्ते में समेट दिया।

टीम इंडिया ने बोर्ड पर टांगे 220 रन

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और उपकप्तान तिलक वर्मा की विस्फोटक अर्धशतकीय पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा आए। वैभव अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। वह 9 गेंदों पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा का बल्ला लगातार दूसरे मैच में भी नहीं चला। अभिषेक 8 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए।

ईशान किशन की शानदार पारी

इसके बाद ईशान और श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की। अय्यर 20 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुए।

दूसरे दिन बेहला और एमपी एकेडमी की जीत

ग्वालियर,25 जुलाई 2026। चौथी हॉकी इंडिया जूनियर विमेन एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन-ए और बी) में दूसरे दिन,भाई बेहला हॉकी एकेडमी भगता और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अपने-अपने पूल-बी मुकाबलों में जीत हासिल की। ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित प्रतियोगिता में शनिवार को पूल-बी के दिन के पहले मैच में, भाई बेहला हॉकी एकेडमी भगता ने शानदार खेल दिखाते हुए मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के विरुद्ध 4-0 से जीत दर्ज की। दीपा उपाध्याय (3') ने शुरुआत में ही गोल दागा, जिसके बाद जसकरणदीप कौर (13'), देविका (56') और पुनीता (58') ने गोल दागकर अपनी टीम को आसान जीत दिलाई।

नोआ लाइल्स ने जीता 100 मीटर यूएस खिताब, 9.77 सेकंड में रचा इतिहास

न्यूयार्क,25 जुलाई 2026।ओलंपिक चैंपियन नोआ लाइल्स ने (स्थानीय समय) को 2026 ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस 9.77 सेकंड में जीतकर दुनिया के सबसे बेहतरीन स्प्रिंटर के तौर पर अपनी पहचान पक्की की। यह इस इवेंट में उनका तीसरा नेशनल खिताब था। 2018 और 2024 में मिली जीत के बाद, लाइल्स ने इस बार भी जीत हासिल की। आइकान स्टेडियम में हुई इस रेस में शुरुआत धीमी रहने के बावजूद, उन्होंने आखिर में तेज़ी दिखाते हुए बाकी सभी को पीछे छोड़ दिया। फिनिश लाइन पार करते ही 29 साल के लाइल्स ने अपने खास अंदाज़ में जश्न मनाया। रॉनी बेकर 9.88 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मौजूदा चैंपियन और दो बार के ओलंपिक 200 मीटर मेडलिस्ट केनी बेडनारेक ने भी 9.88 सेकंड का समय लिया और तीसरे स्थान पर रहे। लाइल्स के ट्रेनिंग पार्टनर और 2019 के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन 9.93 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर रहे। जीत का यह समय जमैका के ओब्लिक सेविल द्वारा पिछले महीने जमैका चैंपियनशिप में बनाए गए 9.82 सेकंड के रिकॉर्ड से बेहतर था, जिससे यह इस साल की सबसे तेज़ 100 मीटर रेस बन गई। लाइल्स ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान अच्छे संकेत मिलने के बाद उन्हें 9.80 सेकंड से कम समय में रेस पूरी करने की उम्मीद थी। इस अमेरिकी एथलीट का मानना है कि लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों की तैयारी शुरू होने के साथ ही, इस प्रदर्शन से उनके प्रतिद्वंद्वियों को एक कड़ा संदेश मिला है। उन्होंने कहा, ÷मुझे लगता है कि मैंने यह साबित कर दिया है कि मैं अभी भी दुनिया का सबसे तेज़ इंसान हूँ। मुझे लगता है कि मैं मज़ाक-मज़ाक में खेल रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि अब हर कोई सतर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर वे मज़ाक कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि जीत तो मेरी ही होगी।÷

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रितमभरा सिंह आ. लखन सिंह, निवासी वार्ड क्रमांक 16, नवापारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा अपनी माता स्व. मंजू सिंह जो प्रा.शा. उरांवपारा,परसा में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थी जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान दिनांक 04.02.2025 को हो जाने के कारण उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र श्रीमान अपर कलेक्टर,अम्बिकापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/08/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक:- 21/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा,छ.ग.

GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, AMBIKAPUR
(A constituent college of CSVTU Bhilai)
DIGMA, AMBIKAPUR, SURGUJA – 497001 (CHHATTISGARH)
Email: gecprincipalambikapur@gmail.com
Website: www.vecambikapur.ac.in Ph. 07774-299183
ADMISSION NOTIFICATION : 2026-27

No./580/GEC/2026 Date-24/07/2026

B. Tech. & M. Tech. Programs for *Working Professionals*

B. Tech.
✓ Civil Engineering
✓ Electrical Engineering
✓ Mining Engineering

M. Tech.
✓ Structural Engineering
✓ Power System & Control
✓ Mining Engineering

1st Time in Chhattisgarh in Govt. Institute B.Tech & M.Tech for Working Professionals

KEY HIGHLIGHTS
➤ **Fee Structure:** As per CG Government Rules.

ELIGIBILITY
➤ Employment: Working in Registered Industry / Govt. / Semi-Govt. / Private / MSME.
➤ Distance: Max 75 KM from GEC Ambikapur (Residence or Workplace).
➤ Experience: Min. 1 year of regular/full-time work experience.
➤ NOC: Permission/No Objection Certificate from current employer is mandatory. Reservation: 1 seat per program for Central Govt. / PSU employees.
➤ Last date of admission – as per CGDTE rule.
➤ Educational Qualification for B.Tech. & M.Tech Admission: As per the Chhattisgarh B.Tech. & M.Tech Admission Rules, 2023 (as amended)

For Admission
Contact Us Now:
Office
☎ 07774-299183
Dr. H. R. Suryawanshi
☎ 8435100206

G.N.- 262702358/1

इस्तीफे पर दीपक बैज का हमला

बोले...कुर्सी बचाने के लिए लिया फैसला

रायपुर,25 जुलाई 2026। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक मजबूरी में लिया गया फैसला है।

छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर साधा निशाना

दीपक बैज ने कहा कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के कई शहरों तक छात्र और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि, केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। बैज के मुताबिक, सरकार ने संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना।

प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए लिया गया फैसला

दीपक बैज ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी नैतिक जिम्मेदारी के तहत नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। बैज ने आरोप लगाया कि बढ़ते जनदबाव और सरकार पर बन रहे राजनीतिक दबाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार से उठाए सवाल

कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक छात्रों की मांगों की अनदेखी की गई। यही वजह है कि देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए।

मवेशियों की तस्करी मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

ट्रायल पूरा होने तक सिर्फ पंजीकृत गौशाला या गोरक्षण संस्थान को ही सौंपे जाएंगे जब्त पशु

बिलासपुर,25 जुलाई 2026। तस्करी और कत्लखाने ले जाए जा रहे कृषि में उपयोग होने वाले मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि मुकदमा चलने के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए मवेशियों की सुपुर्दगी किसी भी निजी व्यक्ति, वाहन चालक या उसके कथित मालिक को नहीं दी जा सकती। जब तक मामले की सुनवाई यानी ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, तब तक जब्त मवेशियों को सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत गौशाला, गोसदन या गोरक्षण संस्थान की कस्टडी में ही रखा जाएगा। दरअसल, जशपुर जिले के मनोरा पुलिस चौकी में ट्रक क्रमांक एचआर 55 क्यू 5980) को पकड़ा था गया था। ट्रक में 23 नर और 5 मादा भैंसों को छत्तीसगढ़ से झारखंड के कत्लखाने ले जाया जा रहा था।

सीजेएम और सेशन कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी

इसके बाद मवेशियों के मालिक गुमला झारखंड निवासी मो. वसीम कुरैशी ने अदालत से मवेशियों को सुपुर्दनामे पर मांगने के लिए अर्जी लगाई थी। सीजेएम जशपुर और फिर सेशन कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

निचली अदालतों के आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने पूर्व के जलील अंसारी बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताते हुए प्रकरण को बड़ी पीठ (लार्जर बेंच) के पास भेज दिया।

कानून का उद्देश्य खत्म हो जाएगा: हाईकोर्ट

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 7 और 18 स्पष्ट रूप से कहती हैं कि मुकदमे के अंतिम निर्णय तक जब्त पशुओं को पंजीकृत गौशालाओं की अभिरक्षा में रखा जाएगा। अदालत ने कहा कि यदि पशुओं की तस्करी के आरोपियों को ही मवेशी वापस सौंप दिए जाएं।

सीजीपीएससी भर्ती घोटाला : ईडी ने टामन सोनवानी को किया गिरफ्तार,कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर सौंपा

रायपुर,25 जुलाई 2026। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को ईडी ने पेपर लीक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और रायपुर की स्पेशल कोर्ट से सोनवानी की एक सप्ताह की रिमांड मांगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 7 दिन की रिमांड पर सौंपा है। सीबीआई जांच के बाद अब ईडी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। इस संबंध में एजेंसी सोनवानी से सभी पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान भर्ती प्रक्रिया में हुए पैसों के लेन-देन, अवैध कमाई और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोनवानी को सात दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा है।

सीबीआई पहले ही कर चुकी है गिरफ्तारी

बता दें कि टामन सिंह सोनवानी को सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई ने दो साल पहले गिरफ्तार किया था। उनके साथ बजरंग पावर एंड स्टील लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों पर चयनित कराने के लिए कथित तौर पर अवैध लेन-देन किया गया था। अब ईडी इस मामले की गहन जांच कर रही है।

सीबीआई की जांच में क्या सामने आया ?

सीबीआई के मुताबिक,टामन ने परीक्षा के पर्चे अपने घर पर साहिल, नीतेश,उसकी पत्नी निशा कोसले और दीपा आडिल को दिए। इसके बाद उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर ने लीक हुआ पेपर बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी के डायरेक्टर श्रवण गोयल को सौंपा। श्रवण गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका ने इसी लीक पेपर से तैयारी की। परिणामस्वरूप दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। CGPSC ने 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। प्री-एग्जाम 13 फरवरी 2022 को कराया गया। इसमें 2 हजार 565 पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई मेंस परीक्षा में 509 अभ्यर्थी पास हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी। आरोप है कि आयोग की परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता को दरकिनार कर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस दौरान योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर डिप्टी कलेक्टर,डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों पर अपने नजदीकी लोगों को पद दिलवाने का खेल हुआ। प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी। जांच एजेंसी ने छापेमारी में कई दस्तावेज और आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए हैं। अब ईडी भी इस मामले में जांच करेगी।

रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड 5 अगस्त तक बढ़ी

जेल जाने से पहले भूपेश बघेल ने की मुलाकात

रायपुर,25 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट पहुंचे और जेल भेजे जाने से पहले रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से सरकार केंद्रीय व राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

ईओडब्ल्यू और ईडी के अनुसार,रामगोपाल अग्रवाल पर शराब घोटाले,कोल लेवी (कोयला लेवी) और कस्टम मिलिंग से जुटाए गए अवैध पैसों को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोयला घोटाले से जुड़े 52 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में देवेंद्र डड़सेना की भूमिका रही है। रामगोपाल अग्रवाल और देवेंद्र डड़सेना से करीब तीन घंटे तक संयुक्त पूछताछ की गई थी, लेकिन रामगोपाल किसी भी तरह की राशि के ट्रांसफर से इनकार किए। जांच एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के माध्यम से कोयला,शराब और कस्टम मिलिंग घोटालों से जुड़े करीब 800 करोड़ रुपये इधर-उधर ट्रांसफर किए गए। हालांकि रामगोपाल अग्रवाल इन सभी आरोपों को खारिज किए थे। कोयला घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया है।

इस मामले में वे न्यायियक रिमांड पर थे। आज रिमांड खत्म होने पर रामगोपाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 5 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी गई है। बता दें कि रविवार को जांच एजेंसी रामगोपाल अग्रवाल को सेंट्रल जेल ले गई थी, जहां शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब कारोबार में करीब 3,400 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

आठ जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल ने किया था सरेंडर

बता दें कि कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल करीब तीन साल तक फरार रहे। 8 जुलाई को उन्होंने ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया था। इसके बाद मेडिकल परीक्षण कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 9 जुलाई से 17 जुलाई तक की पुलिस रिमांड मंजूर की गई थी। रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया और अब 5 अगस्त तक ईओडब्ल्यू की कस्टडी में भेज दिया गया है।

सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में ईडी की एंट्री

मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से तेज हुई जांच

रायपुर,25 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और बहुचर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्रारंभिक जांच के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की आधिकारिक तौर पर धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। सीबीआई की लंबी जांच-पड़ताल और शुरुआती खुलासों के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे प्रकरण में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की बेहद गहराई से जांच करने जा रहा है। इस नए राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम के बाद से राज्य के प्रशासनिक गलियारों में भारी हड़कंप मच गया है और आरोपियों की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी सिलसिले और जांच को आगे बढ़ाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के पूर्व चेयरमैन एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार करने की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के लिए रायपुर की एक विशेष अदालत में औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अदालत में इस याचिका और आवेदन को लेकर लगातार सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है, जिस पर जल्द ही कोई बड़ा और महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यदि माननीय अदालत प्रवर्तन निदेशालय को टामन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी और रिमांड की अनुमति प्रदान कर देती है, तो जांच एजेंसी इस पूर्व चेयरमैन को अपनी कस्टोडियल रिमांड पर लेकर व्यापक स्तर पर पूछताछ करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस कड़ाई से होने वाली पूछताछ के दौरान भर्ती प्रक्रिया में हुए भारी पैसों के लेन-देन, अवैध रूप से की गई अकूत कमाई और इससे जुड़े पूरे वित्तीय नेटवर्क का बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है।

बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत,खेत में धान की रोपाई लगाते समय हुआ हादसा

कोरबा,25 जुलाई 2026। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के सलोरा-छुरी गांव में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से तीन किसानों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ,जब किसान खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। घटना छुरी बकरा बाजार सब-स्टेशन के पीछे स्थित खेत की है। जानकारी के अनुसार, शनिवार को गांव के करीब 25 से 30 किसान एक साथ खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान खेत की मेढ़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से तीन किसान गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद खेत में मौजूद अन्य किसानों ने तीनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कटघोरा पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बहुरन पाटले, लक्ष्मीचंद पटेल और श्याम साहू के रूप में हुई है। तीनों सलोरा-छुरी गांव के रहने वाले थे और आपस में रिश्तेदार थे। मृतक के एक बेटे ने बताया कि खेत में कई लोग काम कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा दुर्लभ सफेद करैत,प्रकृति का अनमोल खजाना आया सामने

दुर्ग,25 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ की जैव विविधता के लिए एक बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। दुर्ग जिले के चरोदा क्षेत्र स्थित पंचशील नगर के एक घर से वन विभाग ने एक ऐसे करैत सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू किया है जो सामान्य काले-पीले रंग का नहीं बल्कि पूरी तरह सफेद है। भौगोलिकसंदर्भ विशेषज्ञों ने जांच के बाद इसे अत्यंत दुर्लभ श्वेतवर्णी करैत Leucistic Common Krait Bungarus fasciatus बताया है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के सर्प का मिलना राज्य की समृद्ध जैव विविधता का बड़ा प्रमाण माना जा रहा है।

घर में मिला सफेद सर्प, रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर : वन विभाग के अनुसार पंचशील नगर के एक मकान में सफेद रंग का सांप देखे जाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद दुर्ग वनमंडल की टीम और सर्प रेस्क्यूअर विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान सर्प के असामान्य सफेद रंग ने सभी का ध्यान खींचा। बाद में सर्प विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह श्वेतवर्णी करैत है। विशेषज्ञों के मुताबिक सर्प का सफेद रंग किसी बीमारी के कारण नहीं है। यह ल्यूसिज्म Leucism नामक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है। इस स्थिति में शरीर में मेलानिन रंगद्रव्य की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे जीव का प्राकृतिक रंग सफेद या हल्का हो जाता है। इसकी आंखों का रंग सामान्य रहता है, इसलिए इसे एल्बिनो से अलग माना जाता है।

दक्षिण एशिया में बेहद कम मिलता है ऐसा करैत : वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि श्वेतवर्णी करैत के मामले पूरे दक्षिण एशिया में बहुत कम दर्ज हैं। अब तक इसके रिकॉर्ड नेपाल, महाराष्ट्र और ओडिशा के कुछ सीमित क्षेत्रों से ही मिले हैं। ऐसे में दुर्ग में इसका मिलना वैज्ञानिक अध्ययन और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है। विशेषज्ञों की पुष्टि के बाद दुर्ग वनमंडलाधिकारी दिपेश कपिल के निर्देश पर इस दुर्लभ सर्प को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।

छत्तीसगढ़ में बढ़ सकता है बस किराया...

यातायात महासंघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

रायपुर,25 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में बस किराए को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों, संचालन लागत में इजाफा और यात्री किराए में की गई कथित कटौती के विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने मांग की है कि साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत तथा डिलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। संगठन का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो 3 अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा और आगे चलकर बस संचालन भी पूरी तरह बंद किया जा सकता है।

परिवहन विभाग के आदेश पर महासंघ ने जताई आपत्ति : यातायात महासंघ का आरोप है कि परिवहन विभाग ने 11 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से बस किराए में लगभग 25 प्रतिशत की कमी कर दी। विभाग ने इस फैसले के पीछे उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया, लेकिन महासंघ का कहना है कि न्यायालय ने केवल किराए को चिल्हर की समस्या से बचाने के लिए राउंड फिगर में निर्धारित करने का निर्देश दिया था। संगठन का दावा है कि अदालत ने कहीं भी किराया कम करने का आदेश नहीं दिया था, फिर भी विभाग ने आदेश की गलत व्याख्या करते हुए किराया घटा दिया,जिससे बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

सुरक्षा उपकरणों से भी बढ़ा संचालन खर्च : महासंघ ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई नए उपकरण अनिवार्य किए गए हैं। इनमें वीएलटीडी,स्पीड गवर्नर,पैनिक बटन, रेडियम पट्टी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। संगठन का कहना है कि इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इन्हें लागू करने से बस संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। महासंघ का दावा है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक बस संचालक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कई लोगों के लिए नियमित रूप से बसों का संचालन करना मुश्किल हो गया है।

बैठक के बाद भी नहीं निकला समाधान : यातायात महासंघ का कहना है कि लगभग पांच महीने पहले परिवहन मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पर बैठक हुई थी। बैठक में बस संचालकों की समस्याओं और किराया संशोधन पर चर्चा हुई थी,लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। संगठन का आरोप है कि लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इससे बस संचालकों में नाराजगी बढ़ी है और कई लोग अपने वाहन खड़े करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

महासंघ ने रखीं प्रमुख मांगें : महासंघ ने सरकार से मांग की है कि 30 सितंबर 2021 के राजपत्र को आधार मानते हुए साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डिलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत की वृद्धि की नई अधिसूचना जल्द जारी की जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र की तर्ज पर ऐसा स्थायी कानून बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें डीजल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार बस किराए का स्वतः निर्धारण किया जा सके।

बढ़ती लागत से बस संचालन हुआ मुश्किल

महासंघ के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में परिवहन व्यवसाय की लागत में लगातार वृद्धि हुई है। सितंबर 2021 के बाद से बसों के चेसिस, बॉडी निर्माण, डीजल,टायर,बीमा,स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव का खर्च काफी बढ़ चुका है। इसके अलावा चालक और परिचालकों के वेतन में भी वृद्धि हुई है। संगठन का कहना है कि इन सभी कारणों से बस संचालन पहले की तुलना में कहीं अधिक महंगा हो गया है, जबकि किराया कम होने से आय प्रभावित हुई है। ऐसे में अधिकांश बस संचालकों के लिए व्यवसाय चलाना कठिन होता जा रहा है।

शराब घोटाले से जुड़े ओवरटाइम स्कैम में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दी

बिलासपुर,25 जुलाई 2026। शराब घोटाला मामले से जुड़े ओवरटाइम स्कैम में 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी संजीव जैन और राजीव द्विवेदी समेत चार आरोपियों को 10-10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण तर्क रखते हुए सबसे प्रमुख मुद्दा सिद्धार्थ सिंघानिया की भूमिका को लेकर उठाया गया। बचाव पक्ष ने कहा कि संबंधित कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया। वहीं, कंपनी के निदेशकों को आरोपी बना दिया गया, जबकि उनकी भूमिका अलग थी। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के मूल अपराध में संजीव जैन को गवाह बनाया गया था, लेकिन उसी मामले से निकले कथित ओवरटाइम घोटाले में उन्हें आरोपी बना दिया गया। यह भी दलील दी गई कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया के हाथ में था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा, कि जांच पूरी हो चुकी है और 18 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोपी ईओडब्ल्यू के नोटिस पर लगातार उपस्थित होते रहे और जांच में पूरा सहयोग करते रहे। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के करीब 18 महीने बाद,4 मई 2026 को उनकी गिरफ्तारी की गई। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इसी मामले के एक अन्य सह-आरोपी को पहले ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर भी आरोपियों को राहत दिए जाने की मांग की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की कथित भूमिका प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती, बल्कि मामले में दबावपूर्वक वसूली किए जाने के आरोप हैं। साथ ही जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में नियमित जमानत देने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों को नियमित जमानत दी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)